आर.एन.आई.नं. RAJHIN/2004/14674

अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर से प्रकाशित राज्य स्तरीय दैनिक

हुक्मनामा समाचार

वर्ष 22 : अंक 83 : मूल्य 2 रु. : पृष्ठ संख्या 8

www.hukmnamasamachar.com | अजमेर, गुरूवार, 12 फरवरी, 2026 | www.Lokvarta.net

2 घंटे 54 मिनट के भाषण में दीया ने किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं

बजट 2026-27

राहत और तोहफे का खुला पिटारा

दिया कुमारी ने पेश किया बजट

ऊर्जा, पानी, महिला, युवा पर रहा फोकस

6.11 लाख करोड़ का बजट

इस बार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ का बजट पेश किया है। पिछली बार बजट का साइज 5 लाख 58 हजार 596 करोड़ था। इस बार बजट का साइज पिछली बार से 52 हजार 360 करोड़ ज्यादा है।

कृषि बजट में बढ़ोतरी

दीया कुमारी ने कहा- कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें 69 हजार करोड़ समेकित निधि से खर्च होंगे। यह पिछले साल से 7.59 प्रतिशत ज्यादा है। कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है।

गाड़ियों पर लगेगा कम टैक्स

- दीया ने कहा- सरकार ने कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया है।
- बजट में अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टैक्स में कमी की गई है।
- अब सरकारी भवनों के निर्माण में 50 प्रतिशत तक एम सैंड का इस्तेमाल होगा, इसे 25 फीसदी से बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत किया गया।
- वैट, भूमि कर, खनन, परिवहन से जुड़े बकाया टैक्सों के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाई जाएगी।
- 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।
- लॉजिस्टिक सेंटर्स को भी अब रिप्स-2024 का लाभ मिलेंगे, कस्टमाइज पैकेज और छूट मिलेंगी।

किसानों को ब्याज मुक्त ऋण

- 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिए जाएंगे।
- इसके लिए 800 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
- 5 लाख पशुपालकों को दूध पर बोनस पर 700 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
- यूपी, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे।
- हर पंचायत स्तर पर नमो वन विकसित होंगे, नमो नर्सरी खोली जाएंगी।

किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली

- बजट में किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा - शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू होगा।
- बीसलपुर के दायीं मुख्य नहर के 5000 हेक्टेयर के कमांड एरिया में 100 करोड़ की लागत से फव्वारा सिंचाई प्रणाली का लाभ मिलेगा।
- अगले साल 50 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे, 1500 करोड़ खर्च होंगे। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
- 8000 डिग्गियों का निर्माण होगा। 36 हजार नए फार्म पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान मिलेगा, 80 हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
- 50 हजार किसानों को तारंबदी के लिए 288 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा

- 8 नए जिलों, नई पंचायत समितियों में सरकार दफ्तर बनाने, 3467 नई ग्राम पंचायतों में विकास कामों के लिए 3000 करोड़ की लागत से विकास के काम होंगे।
- ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे,अब तक ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार नहीं हैं।
- मुख्य सचिव दफ्तर में डिरेगुलेशन सेल भी बनाई जाएगी। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोला जाएगा।
- शहरों में होमगार्ड की नफरी 5000 तक बढ़ाई जाएगी, इससे होमगार्ड को ज्यादा काम मिलेगा।
- उपनिवेशन विभाग खत्म होगा, उपननिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय होगा।
- गृह विभाग का रिवॉल्विंग फंड बढ़कर 7 करोड़ किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी, 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा,अरावली बचाने के लिए 130 करोड़ खर्च होंगे

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं।

उन्होंने कहा- 8वें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी बनाई जाएगी। परीक्षाओं के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी का भी बजट में ऐलान किया। सरकार स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारा भी देगी। असहाय, विमंदित, लावारिस मरीजों को अब फ्री इलाज मिलेगा। बजट में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में अब कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया है। वित्त मंत्री ने कहा- सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसकी पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। साथ ही कर्मचारी के सरकारी नौकरी में रहते समय स्थायी दिव्यांग हो जाती है और वह नौकरी करने में असमर्थ है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। साथ ही नई जल नीति लाने का भी ऐलान किया गया। करीब 6500 गांवों को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी। 4 जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा। अगले साल 15 नए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी। झींगा पालने वाले किसानों को सस्ती बिजली भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट का भी ऐलान किया है।

4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग

- बजट में जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र शुरू करने की घोषणा की गई है।
- थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा, इसमें पश्चिमी रेगिस्तानी जिले शामिल होंगे।
- दीया कुमारी ने बजट में भरतपुर में बृज कन्वेंशन सेंटर, झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम की भी घोषणा की।
- उन्होंने कहा कि 50 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
- मंदिरों में विशेष पूजा के लिए 13 करोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत होगी।
- देवस्थान की जमीनों पर बीओटी आधार पर धर्मशालाएं बनेंगी।

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नई योजना

- गंभीर मरीजों और एक्सीडेंट के मामलों में तत्काल इलाज के लिए राज सुरक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी।
- एक्सीडेंट में तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर्स पर एंबुलेंस तैनात की जाएगी।
- आत्महत्याएं रोकने और मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू होगा।
- एसएमएस में मेंटल हेल्थ पर नया सेंटर खुलेगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ केयर सेंटर खुलेंगे।
- कॉलेजों में मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग के लिए काउंसलर जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे।

ड्रोन के लिए नई पॉलिसी लाएगी सरकार

- गवर्नेंस सेक्टर में भी दीया कुमारी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा- 25 हजार महिलाओं और युवाओं को मिनी ई मित्र के तौर पर अधिकृत किया जाएगा।
- नई आईटी पॉलिसी भी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि- सीएम प्रमाण सेंटर की स्थापना होगी। नीति आयोग की तर्ज पर बने रीती पर अगले साल 10 करोड़ खर्च होंगे।
- राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाएगा। सरकारी नई ड्रोन पॉलिसी भी बनाएगी।
- सरकारी जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मरुधरा राज भूमि डिजिटल एड्रेस बनाया जाएगा।

पानी की समस्या से निपटने के नए ऐलान

गर्मी में पर्याप्त पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगेंगे। समर कंटिजेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1-1 करोड़ मिलेंगे। 10 करोड़ की लागत से पानी पद जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू होगा। राजस्थान की नई जल नीति लाई जाएगी। जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती होंगी करीब 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल की सुविधाएं विकसित होंगी। अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए।

50 हजार युवाओं को होगा फायदा

दीया कुमारी ने कहा कि- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा। इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा दिया जाएगा। राज सवेरा के नाम से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

इन जिलों में खुलेंगे 15 नए कोर्ट

राजस्थान बजट 2026 में प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को मजबूत और सुलभ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कानून व्यवस्था के साथ-साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया है। धोरीमन्ना (बाड़मेर), नीमराणा (कोटपूतली-बहरोड़), इटावा (कोटा), तारानगर (चूरू) और खाटूश्याम (सीकर) में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जाएंगे। इससे इन इलाकों के लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा।

प्रदेश के कई जिलों में बनेंगे स्टेडियम

प्रदेश के ब्यावर, कोटपूतली- बहरोड़, बासवाड़ा, डीग, चित्तौड़गढ़, जालोर, राजसमंद, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सीकर और बारां में नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। जयपुर चित्रकूट स्टेडियम और ब्यावर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही कई पुराने स्टेडियमों का पुनर्विकास भी किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 2500 से अधिक ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जाएंगे। इससे गांव के नौजवानों को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, जयपुर में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के लिए अगले साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

पेनल्टी कॉर्नर

पटेला री पोल

बजट आया प्रदेश का, उम्मीदे थी इससे बहुत ज्यादा
बातें ज्यादा रह गई इसमें, मिला उम्मीद से भी आधा
आंकड़ों का यह मायाजाल, समझ में आती आधी बात
जनता को मुर्ख बनाते, घोषणा अधूरी पर कर की पूरी घात

....मुखिया जी

राज्य बजट 2026-27 पर मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित : राज्य बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज

प्रदेश का समग्र एवं सतत विकास होगा सुनिश्चित : भजनलाल

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं-आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के तीन कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए बनाया गया है। यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है।

बुधवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि के दिन आया यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण सहित बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

10 स्तम्भों पर आधारित हमारा बजट

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तिकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मजबूत स्तम्भों पर आधारित है।

परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी सुनिश्चित

शर्मा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी तरीके से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करने के क्रम में अब तक 1 लाख से अधिक को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया है। वहीं, निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

वीबी जी राम जी में 4 हजार करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 76 लाख किसानों के खातों में 10 हजार 900 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी की गई है। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे। रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

जिला स्तर पर खुलेंगे रूरल महिला बीपीओ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तथा लखपति दीदी योजना में ऋण को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख आदि प्रावधान महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक होंगे।

CMYK

कुरुक्षेत्र में हुआ संस्कृति, परंपरा और भारतीय सभ्यता का उत्सव

कुरुक्षेत्र के पीपली में 12 दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ आयोजित

डीडवाना (हुक्मनामा समाचार)। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली में महर्षि दयानंद सरस्वती एवं स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान शताब्दी वर्ष के शुभारंभ पर 12 दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ आयोजित हुआ। इस आयोजन में वर्ल्ड पीस हार्मनी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी शिरकत की।इस दौरान कार्यक्रम संयोजक स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती, सुभाष सुधा जी (पूर्व राज्य मंत्री हरियाणा), उस्ताद डॉ. मुजतबा हुसैन (अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बांसुरी वादक), आलोक कुमार (अध्यक्ष, अन्तरराष्ट्रीय विश्व हिन्दू परिषद) अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा अनेक संत महात्माओं, विद्वान जनों तथा श्रद्धालु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के साथ ही अनेक राज्यों से धर्मप्रेमी ओर भक्तजन भी पहुंचे, जिससे यह कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि संस्कृति, परंपरा और भारतीय सभ्यता के उत्सव में बदल गया। इस मौके पर वर्ल्ड पीस हार्मनी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं खुशनसीब हूं, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती जैसे पवित्र अवसर पर अपने विचार रखने का अवसर मिला। मैं धर्म से मुस्लिम हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस देश का नागरिक हूं, और हम सबकी पहचान सबसे पहले इंसानियत से होती है। आजाद ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया, अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा, विशेषकर नारी शिक्षा पर ज़ोर दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का असली अर्थ है – सत्य, नैतिकता और मानव कल्याण। आजाद ने कहा कि सनातन धर्म की जो मूल भावना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की है। यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यही बात इस्लाम भी सिखाता है कि पूरी इंसानियत एक परिवार की तरह है और हमें आपस में प्रेम, भाईचारा और सम्मान बनाए रखना चाहिए। जब हम इन मूल्यों को देखते हैं तो महसूस होता है कि अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंज़िल सबकी एक ही है — अच्छाई, शांति और इंसानियत। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज सुधार के लिए जो संघर्ष किया, वह किसी एक समाज के लिए नहीं था, बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए था। उन्होंने शिक्षा को ताकत माना और ज्ञान को सबसे बड़ा प्रकाश बताया। आज के समय में हमें भी उसी प्रकाश को आगे बढ़ाना है — बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, समाज से बुराइयों को दूर करना और आपसी सौहार्द बनाए रखना।गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज जब हम उनकी जयंती मना रहे हैं और 12 दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ जैसे भव्य आयोजन में एकत्रित हुए हैं, तो यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे मूल्यों का उत्सव है।

साादिया की उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने किया स्वागत सत्कार

सादिया सैयद ने जीता सिल्वर मेडल सीबीएसई डब्ल्यूएसओ गेम्स में सॉफ्टबॉल में जीता सिल्वर मेडल

डीडवाना (हुक्मनामा समाचार)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में डीडवाना की सॉफ्टबॉल खिलाड़ी सादिया सैयद पुत्री सैयद आरिफ अली ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल जीतकर डीडवाना का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि बिलासपुर में 4 से 8 फरवरी तक 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, विद्याभारती, मणिपुर, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू काश्मीर, तमिलनाडू, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व बिहार के 576 से अधिक बालक-बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान साफ्टबॉल अंडर 17 बालक-बालिका प्रतियोगिता में डीडवाना की सादिया सैयद ने सॉफ्टबॉल के अंतर्राष्ट्रीय कोच सैयद शाकिर अली व मार्गदर्शक सुबोध मिश्रा के निर्देशन में सीबीएसई डब्ल्यूएसओ की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर सादिया ने शानदार व उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए उपविजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर सादिया सैयद को सिल्वर मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सादिया सैयद के दादा स्व. सैयद नासिर अली फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए सादिया ने सॉफ्टबॉल खेल को चुनकर परिश्रम किया। सादिया के सिल्वर मेडल जीतकर डीडवाना लौटने पर उनके पिता सैयद मोहम्मद आरिफ, ताऊजी सैयद आसिफ अली, सैयद मोहम्मद फारूक सहित अनेक खेल प्रेमियों ने स्वागत सत्कार किया।

राजकीय बालिका विद्यालय में सुरक्षा जागरूकता अभियान, छात्राओं को बताए हेल्पलाइन नंबर व सिटीजन ऐप की जानकारी

अजमेर (हुक्मनामा समाचार)। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर अजमेर में बुधवार को छात्राओं की सुरक्षा, जागरूकता एवं डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर विशेष अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कालिका टीम-3 की सदस्य पूजा (2090) एवं सावित्री (2697) ने विद्यालय पहुंचकर छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी तथा राजकोट सिटीजन ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करना सिखाया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा अथवा अन्य आपात स्थिति में तुरंत संबंधित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि समय पर सूचना देने से गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।पूजा ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं का जागरूक और तकनीकी रूप से सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है।

मोबाइल तकनीक का सही उपयोग कर छात्राएं अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर सकती हैं। उन्होंने सिटीजन ऐप की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके माध्यम से शिकायत दर्ज करना, पुलिस सहायता प्राप्त करना तथा आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करना सरल और सुलभ है। सावित्री ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देते हुए कहा कि भयभीत होने के बजाय हर समस्या का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर बालिकाओं के लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं, जिनका सही उपयोग उन्हें सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। छात्राओं ने बड़ी संख्या में अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया और उसके संचालन की जानकारी प्राप्त की। कई छात्राओं ने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं। भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न

झालावाड़ (हुक्मनामा समाचार)। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन बुधवार को जिला परिषद सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड द्वारा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सीएचओ से शत-प्रतिशत कार्य करवा कर जिले को प्रथम स्थान पर लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। विशेष रूप से आभा कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, टीकाकरण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना, क्षय रोग नियंत्रण, लाडो प्रोत्साहन अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से आमजन तक पहुंचाई जाएं। उन्होंने टीकाकरण की शत-प्रतिशत उपलब्धि, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाए। नसबंदी महिलाओं के बकाया शुल्क आगामी सात दिवस पर जमा हो। लाडो प्रोत्साहन योजना की जिला स्तरीय रैंकिंग प्रथम बनी रहे। जिन ब्लॉक के आरसीएच गतिविधियों की रैंक कम है, उन पर विशेष शिविर लगाकर वहां पर टीकाकरण व अन्य कार्य करवाने के लिए बीसीएमओ को निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर आई रेड का प्रशिक्षण दिया गया। जिससे जिले में दुर्घटनाओं को रोकथाम व मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने विभागीय गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमएचओ ने बताया जिले में सभी चिकित्सालय में विशेषज्ञों द्वारा अपने संबंधित विभागों में ज्वाइन कर लिया गया है। जिससे चिकित्सा सेवाएं और सुदृढ़ हो रही है।

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के तहत गोपाल नगर में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम

चित्तौड़गढ़ (हुक्मनामा समाचार)। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के अंतर्गत इस वर्ष के मुख्य विषय सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम' पर ग्राम पंचायत मानपुरा के अंतर्गत गोपाल नगर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को की प्रक्रिया तथा उसके महत्व की विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान का सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव एवं सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार पर भी जागरूक किया गया। वक्ताओं ने बताया कि समय पर अपडेट कराना न केवल बैंकिंग सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव का भी एक प्रभावी माध्यम है। इस अवसर पर के जिला स्तरीय अधिकारी सागर पवार, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर परेश टांक, ऋस्श्वञ्रढ्ढ निदेशक अमित चौधरी, स्न्रस्ट काउंसलर विष्णु दत्त, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक डिम्पल बागड़ी तथा ष्टस्न्रु सेंटर मैनेजर शिवलाल बलई उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनने, डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करने तथा बैंकिंग सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं की शंकाओं का समाधान किया गया तथा सुरक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बैंकिंग व्यवहार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

जाति प्रमाण पत्र बनवाना बना आम जनता के लिए सिरदर्द

राजस्थान सरकार की जटिल प्रक्रिया पर समाजसेवी मोहम्मद हारून रंगरेज का बड़ा खुलासा

अजमेर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान में जाति प्रमाण पत्र बनवाना आज आम आदमी के लिए किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है। समाजसेवी मोहम्मद हारून रंगरेज ने जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मोहम्मद हारून रंगरेज का कहना है कि सरकार की तय की गई औपचारिकताएं इतनी जटिल हैं कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति हताश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाता है। मोहम्मद रंगरेज ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को पहले यह साबित करना पड़ता है कि वह ओबीसी जाति से है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म पर दो गजेटेड ऑफिसर के हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं। यही नहीं, आय प्रमाण पत्र पर भी दो गजेटेड ऑफिसर के साइन जरूरी हैं। मोहम्मद हारून रंगरेज ने सवाल उठाया कि आखिर आम आदमी दो-दो गजेटेड ऑफिसर कहां से लाए क्या हर गरीब व्यक्ति के रिश्तेदार गजेटेड अफसर होते हैं हकीकत यह है कि गजेटेड ऑफिसर आमतौर पर ऐसे साइन करने से बचते हैं।

कई बार लोग घंटों दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, फिर भी गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं करते। इसके बाद आवेदक से पट्टा व रजिस्ट्री मांगी जाती है, फिर पटवारी की रिपोर्ट लगती है और अंत में इन सभी दस्तावेजों पर नोटरी पब्लिक से सत्यापन कराना अनिवार्य होता है। मोहम्मद हारून रंगरेज का कहना है कि इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी कई मामलों में 'ऑब्जेक्शन' लगा दिया जाता है और प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता। सबसे गंभीर बात यह है कि जिन लोगों का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, और उनके पिता व दादा का भी जाति प्रमाण पत्र मौजूद है, फिर भी उनका नया या संशोधित जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। वैध दस्तावेज होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा फाइल पर आपत्तियां लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मोहम्मद हारून रंगरेज ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और दलालों को बढ़ावा दे रही है। गरीब आदमी सीधे काम नहीं करवा पाता, मजबूरी में उसे बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। मोहम्मद हारून रंगरेज ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। गजेटेड ऑफिसर के दोहरे हस्ताक्षर की शर्त को हटाया जाए और ऑनलाइन व पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया तो आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज के लिए लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक है।

निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर 22-24 फरवरी को

चित्तौड़गढ़ (हुक्मनामा समाचार)। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से 22 से 24 फरवरी 2026 तक चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित जैन गुरूकुल/धर्मशाला परिसर में 12वां विशाल निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद, महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ चेरिटेबल ट्रस्ट तथा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर (जयपुर फुट) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। शिविर में दुर्घटना में पैर गंवा चुके दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), हाथ गंवा चुके व्यक्तियों के लिए कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराए जाएंगे। पोलियो प्रभावित भाई-बहनों के लिए कैलिपर्स, बैसाखियां एवं तीन पहिया साइकिल (ट्राइसाइकिल), व्हीलचेयर तथा जरूरतमंदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक छड़ी वितरित की जाएगी। बुजुर्ग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए छड़ी एवं श्रवण यंत्र भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आयोजकों ने जिले के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग भाई-बहनों से निर्धारित तिथियों में आवश्यक दस्तावेजों सहित शिविर स्थल पर उपस्थित होकर लाभ उठाने की अपील की है।

श्रीमनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा आयोजन शुरू

मौलासर (हुक्मनामा समाचार)। नजदीकी ग्राम बांसा के आम गुवाड़ में स्तिथ मनोकामनेश्वर महादेव के मंदिर की पांच दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन का शुभारम्भ किया गया. मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन ठाकुर जी मंदिर से कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमे महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर गाजे बाजे की धुन पर नाचती हुई कस्बे के विभिन्न मार्गो से होते हुये बांसा के शिव मंदिर तक पहुँची। मिली जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को भूमि पूजन किया जायेगा, जिसमे सभी देव मंडल की पूजा होगी। मदन पूरी ने बताया कि यज्ञ में यजमानो द्वारा आहुतियां दी जायेगी, वही 13 फरवरी को अग्निदेव पूजन होगा, 14 फरवरी को महायज्ञ का आयोजन किया जायेगा, वही 15 फरवरी को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी,देर रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम में बांसा व निमोद सहित आस पास के शिव भक्त पहुँचे है।

ग्रामीण उत्थान शिविर

निःशुल्क पशु बीमा योजना के अंतर्गत मेरी दो भैंसों का बीमा हुआ है

ग्राम मंगाना (हुक्मनामा समाचार)। ग्रामीण उत्थान शिविर के अंतर्गत 05 फरवरी 2026 को ग्राम मंगाना में राज्य सरकार की निःशुल्क पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम मंगाना निवासी मंजूबाई, पत्नी घनश्याम, को उनकी दो भैंसों की बीमा पॉलिसियाँ प्रदान की गईं। मंजू बाई ने बताया कि पशुपालन उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है और भैंसों से प्राप्त दूध व घी से ही परिवार का भरण-पोषण होता है। मंजू बाई ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा —निःशुल्क पशु बीमा योजना के अंतर्गत मेरी दो भैंसों का बीमा हुआ है, जिससे मेरा परिवार बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। यदि किसी कारणवश भैंस की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा राशि से मैं दूसरी भैंस खरीद सकूँगी और मेरे परिवार को दूध एवं घी की निरंतर उपलब्धता बनी रहेगी। इससे मेरी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। मैं इस जनकल्याणकारी योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूँ।

सफलता की कहानी

ग्रामीण उत्थान शिविर

भादसोड़ा (हुक्मनामा समाचार)। ग्रामीण उत्थान शिविर के अंतर्गत 05 फरवरी 2026 को भादसोड़ा में राज्य सरकार की मंगला पशु बीमा योजना के तहत पात्र पशुपालकों को निःशुल्क पशु बीमा का लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर ग्राम सुथरी खेड़ा (भादसोड़ा) निवासी नारायणी बाई, पत्नी राधेश्याम जाट, की दो भैंसों का निःशुल्क बीमा मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। नारायणी बाई ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा — राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क पशु बीमा योजना के अंतर्गत मेरी दो भैंसों का बीमा हुआ है। इससे मेरा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। यदि किसी कारणवश भैंस की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा राशि से मैं दूसरी भैंस खरीद सकूँगी और मेरे परिवार में दूध एवं घी की उपलब्धता बनी रहेगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

कार्यालय नगरपालिका पीसांगन, जिला अजमेर (राज.)
रिछमालिया रोड़, पीसांगन
E-mail : nagarpalikapisangan@gmail.com

क्रमांक : न.पा.पी./निविदा/2025-26/1821 दिनांक : 09.02.2026

-: ई-निविदा सूचना संख्या (08/2025-26) :-

नगर पालिका पीसांगन द्वारा निम्न कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2025-26 में नगरपालिका क्षेत्र पीसांगन में सी.सी. सडक निर्माण कार्य करवाये जाने की सेवाओं हेतु इच्छुक एंव अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेन्ट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। ई-टेण्डरिंग में न्यूनतम दर को स्वीकार की जायेगी। निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in डाउनलोड एवं अपलोड़ व http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड किये जा सकते है। उक्त निविदा सूचना पोर्टल पर दिनांक 10.02.2026 से देखी जा सकती है।
उक्त कार्य की (NIB Cobe DLB2526B1393)
UBN NO. – (1) DLB2526WSOB33576 (2) DLB2526WSOB33577 (3) DLB2526WSOB33578 (4) DLB2526WSOB33579 (5) DLB2526WSOB33580 (6) DLB2526WSOB33581 (7) DLB2526WSOB33582 (8) DLB2526WSOB33583

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका पीसांगन

राज.संवाद/सी/25/19597

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रदीप लोढा द्वारा एफ बी 3, करतारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया रोड नंबर 4, जयपुर से मुद्रित एवं पीली कोठी, जयपुर गोल्डन, जयपुर रोड, अजमेर से प्रकाशित। फोन 2623396, संपादक - प्रदीप लोढा, प्रबंध संपादक - वैभव लोढ़ा, जयपुर कार्यालय- जी 1, एफ ब्लॉक, गणपति एनक्लेव, अजमेर रोड जयपुर। जोधपुर कार्यालय -902, तीसरी ई रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। फोन 2433621, ई मेल hukmnama.ajmer@gmail.com

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं आज से

19.90 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत, बोर्ड में सीसीटीवी से रखी जा रही नजर, कंट्रोल रूप 24 घंटे जारी, दो फोन नम्बर और जोड़े

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ एवं सचिव श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है।

परीक्षा में 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी पंजीकृत है। प्रदेश के 6194 केन्द्रों पर परीक्षा होगी। बोर्ड सचिव श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष सैकेण्डरी परीक्षा में 10 लाख 68 हजार 109, सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में 9 लाख 10 हजार 9, प्रवेशिका में 7 हजार 817 तथा वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, उड़नदस्तों की तैनाती एवं विशेष दलों की नियुक्ति की गई है। इस साल जिलों में अभय कमांड सेन्टर से भी परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बुधवार शाम बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम व सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। यहां पर्याप्त संख्या में कार्मिक तैनात किए गए हैं। बोर्ड सचिव ने परीक्षार्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने की अपील की है। परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन के लिए शिक्षक, केंद्राध्यक्ष एवं प्रशासनिक अधिकारी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। कन्ट्रोल रूम हुआ 24 घंटे जारी उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम व्यवस्था बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए बोर्ड कार्यालय में 24 घण्टे कार्यरत रहेगा। परीक्षा संबंधी किसी भी शिकायत के लिए नीचे दिए गए दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायतकर्ता अपना नाम, पता, टेलिफोन अथवा मोबाईल नम्बर अवश्य नोट करावें। कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायत का क्रमांक अवश्य प्राप्त करें ताकि इसी शिकायत क्रमांक से समाधान की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। परीक्षार्थियों के नामांक, केन्द्र संबंधी जानकारी बोर्ड वेबसाईट पर उपलब्ध है। बोर्ड कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632668, 4083549, 4083550 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ईमेल आईडी पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 671 अभ्यर्थियों की सूची जारी

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उपनिरीक्षक-दूरसंचार (गृह ग्रुप-1) विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2024 अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। आयोग सचिव ने बताया कि दिनांक 9 नवंबर 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवानियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले कुल 671 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्रता की शर्त पर सूची में सम्मिलित किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा आमंत्रित एवं यथासमय सूचित किया जाएगा।

महिला कांग्रेस का नेतृत्व सजृन शिविर 14 फरवरी को जयपुर में

जयपुर,(हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्का लांबा के नेतृत्व में 14 एवं 15 फ़रवरी को 'नेतृत्व-सृजन' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रिंक्की सिंह हंतरा ने बताया कि शिविर के सफल आयोजन को लेकर आज क्ष्ष्ट में राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सारिका सिंह की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविर महिला कांग्रेस को वैचारिक रूप से सशक्त बनाने एवं नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध होगा। प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे।

भाजपा सरकार की विफलताओं और अजमेर की उपेक्षा, भाजपा सरकार से जवाब मांगता अजमेर

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। राज्य सरकार द्वारा 21.52 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने के बावजूद अजमेर एक बार फिर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। भाजपा सरकार भले ही यह दावा कर रही हो कि पिछले बजट की 1188 योजनाएं धरातल पर उतार दी गई हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कैलाश झालीवाल ने सरकार की नीयत और पारदर्शिता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार को अपने कामकाज पर भरोसा है, तो वह अब तक पूरी हुई योजनाओं की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार की पोल खुलने के डर से योजनाओं की विस्तृत जानकारी और प्रगति रिपोर्ट जनता के सामने नहीं लाई जा रही है। झालीवाल ने कहा कि मंचों से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब बात अजमेर की आती है तो यह विशाल बजट भी सवालों के घेरे में आ जाता है। कौन-सी योजना पूरी हुई, कौन-सी अधूरी है और कौन-सी सिर्फ फाइलों में ही दौड़ रही है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक बजट घोषणा की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट जारी की जाए और घोषित योजनाओं का ऑडिट स्टेटस सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हकीकत यह है कि भाजपा सरकार घोषणाओं से आगे बढ़ने में असफल रही है। ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा अजमेर आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। वादों का शहर बन चुका अजमेर विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है। अजमेर में भाजपा सरकार की प्रमुख विफलताएं : पेयजल संकट, हर बजट में घोषणाएं, लेकिन हर गर्मी में टैंकर राज। सड़कों की बदहाली, स्मार्ट सिटी का तमगा, मगर गड्ढों में डूबा शहर। पर्यटन की उपेक्षा, पुष्कर और दरगाह क्षेत्र के विकास के नाम पर सिर्फ डीपीआर तक सीमित योजनाएं। रोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस जिला-स्तरीय रोजगार योजना नहीं। नगर निगम की अव्यवस्था सफाई, स्ट्रीट लाइट और जल निकासी व्यवस्था बदहाल। कैलाश झालीवाल ने कहा कि इस बजट में भी अजमेर के लिए अलग से कितनी राशि आवंटित की गई है, इसका कोई स्पष्ट जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अजमेर के विकास को लेकर अलग से स्थिति रिपोर्ट जारी की जाए, अपनी विफलताओं को स्वीकार कर सुधार की ठोस दिशा बताई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह बजट भी पिछले बजटों की तरह सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह जाएगा और अजमेर की जनता को एक बार फिर ठगा जाएगा।

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कनेछन कलां में किशोरी शैक्षणिक बाल मेला आयोजित

शाहपुरा। कनेछन कलां, बुधवार। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कनेछन कलां में बुधवार को किशोरी शैक्षणिक बाल मेले का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण कुमावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बृजमोहन महावर, पीईईओ रज्जब अली, सरजीत कुमार, नंद किशोर शर्मा, जीताराम बैरवा, सूर्य प्रकाश शर्मा, नीटू कुमार, प्रहलाद मीणा एवं पवन कुमार जीनगर सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। बाल मेले में स्थानीय छात्राओं द्वारा शिक्षण विषयों पर आधारित लगभग 35 स्टॉल लगाए गए तथा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। मेले में 15 विद्यालयों की करीब 300 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संतरा कुमारी ने बताया कि छात्राओं ने एटीएम मशीन, ईवीएम मशीन, चंद्रयान-3, 'आओ देखो जानो', 'मैं हूं कौन' जैसे विभिन्न शैक्षणिक एवं नवाचार आधारित मॉडल प्रस्तुत किए।

अच्छे संस्कार ही नैतिकता के मार्ग का आधार हैं : डॉ. अतुल

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। 'अच्छी आदतें ही वास्तविक मूल्यों की पहचान होती हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करता है, वही नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर रहता है।' यह कहना था मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद् और राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉ. अतुल कोठारी का जो 'चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला के भव्य उद्घाटन पर सभा को संबोधित कर रहे थे।

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 11 से 13 फरवरी, 2026 तक आयोजित की जा रही है। डॉ. कोठारी ने अपने अभिभाषण में पंचकोश सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश की व्याख्या की तथा प्रत्येक कोश को दैनिक जीवन के सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने प्रतिभागियों को इन कोशों के भावार्थ को आत्मसात करने एवं नियमित अभ्यास द्वारा इन्हें जीवन में उतारने का सुझाव दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश को अपरिहार्य बताया। उन्होंने वर्तमान समय को 'चरित्र संकट' का दौर बताते हुए कहा कि समाज की अनेक समस्याओं की जड़ नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट है, तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य को 'व्यक्ति' इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने विचारों, भावनाओं एवं कर्तव्यों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। डॉ कोठारी ने यह आह्वान किया कि हम सब सीखने की प्रक्रिया में आजीवन विद्यार्थी बने रहें, क्योंकि निरंतर सीखना ही व्यक्तित्व विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि खेलकूद, स्वच्छता एवं अनुशासित जीवनशैली से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं मन को शांत रखना मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान एवं विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से होता है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक व अध्यक्ष, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास केवल एक संस्था नहीं हैं, यह भारत की शिक्षा-आत्मा को पुनर्जीवित करने का आंदोलन हैं। न्यास हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि मनुष्य का निर्माण हैं। प्रो भालेराव ने आगे बताया कि यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यशाला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संकल्प का प्रारम्भ हैं। एक ऐसा संकल्प जो व्यक्ति के भीतर से राष्ट्र के निर्माण तक जाता हैं। न्यास की दृष्टि में शिक्षा का लक्ष्य है - कर्तव्यबोध, संस्कार, राष्ट्र चेतना, सेवा भाव, आत्मा अनुशाशन और सत्यनिष्ठा। कुलपति ने कार्यशाला के विषय पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र का निर्माण केवल सेनाओं से नहीं होता हैं, राष्ट्र का निर्माण चरित्रवान व्यक्तियों से होता हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की ऊंचाई चरित्र की गहराई पर निर्भर करती हैं। यदि चरित्र नहीं हैं, तो व्यक्तित्व केवल प्रदर्शन बनकर रह जाता हैं। और प्रदर्शन बहुत जल्दी टूटता हैं।

ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत शपथ दिलाई

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर बाल विवाह भारत मुक्ति जागरूकता किया गया चाइल्ड हेल्पलाइन बाल अधिकारिकता विभाग अजमेर द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत आज दरगाह बाजार में दरगाह में चाइल्डलाइन एव गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी सहित कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ जन सेवा नूर मोहम्मद कादरी में दिलीप सिंह राठौड़ सरदार भजन सिंह मौलाना गुलाम हुसैन दरगाह थाने से दीवान अर्जुन राम जी महावीर प्रसाद जी चाइल्ड हैडलाइन काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा व सुपरवाइजर कलीम खान जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद रहे कार्यक्रम का में उद्देश्य बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का है चाइल्ड हैडलाइन काउंसलर प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि भारत मुक्त बाल विवाह अभियान के तहत अजमेर के दरगाह बाजार क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर बच्चों, खासकर बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

कांग्रेसियों ने बताया राजस्थान बजट को निराशावादी

अजमेर। उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संपत कोठारी कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष सतीश वर्मा राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकुमार गर्ग पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता डॉ संजय पुरोहित ने राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश राजस्थान सरकार के बजट 2026 27 को निराशावादी बताया है ! कांग्रेसी नेताओं ने राजस्थान बजट 2026 27 प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट ने युवा छात्र महिला श्रमिक किसानों एवं हर वर्ग को निराश किया है। कांग्रेसी नेताओ ने तंज कसते हुए कहा कि पर्ची की सरकार विजन 2047 प्रस्तुत कर रही है जबकि विकास की आवश्यकता आज है।

भाजपा सरकार की सामूहिक विफलताओं पर पर्दा डालने और जनता को भ्रमित करने वाला बजट : राठौड़

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने आज राजस्थान सरकार के पेश बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर बजट को निराशाजनक बताया। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह बजट सिर्फ थोथी घोषणाओं का पिटारा है।

इस बजट प्रदेश के विकास के लिए हवाई बाते की गई, धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आए। राजस्थान सरकार में अजमेर से केबिनेट, राज्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद कोई विकास की सौगात नहीं दी गई। राजस्थान सरकार की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिसने बजट पेश किया है। जबकि वो खुद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री भी है। बावजूद इसके इस बजट में अजमेर की उपेक्षा साफ तौर पर देखने को मिली है। जाहिर है भाजपा के राज में प्रदेश और अजमेर का कोई धोणी धरी नहीं है। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष ने सरकार के बजट पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि, 'कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले ! उस इंक़लाब का जो अब तक उधार है राजस्थान में आज का बजट देखकर प्रतीत होता है कि यह सरकार माध्यम वर्ग व मज़दूर वर्ग के हितों के लिए नहीं उद्योगपतियों के सामूहिक फायदे को लेकर अधिक चिंतित है। राजस्थान की आम जनता को मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि कोई आम आदमी मुख्यमंत्री बना है तो वह इस राज्य की पीड़ा को समझेगा, लेकिन आज के बजट में सबको गहरी निराशा हाथ लगी है। आमजन, किसान, युवा, मज़दूर, छोटे व्यापारी व महिलाओं के लिए यह बजट कोई राहत की खबर बनकर नहीं बल्कि आहत मन को छिन्न भिन्न करने वाला साबित हुआ है। सरकार संवेदनहीन बनकर राज्य की बेशकीमती पूंजी कॉरपोरेट घरानो को लुटा रही है। राठौड़ ने कहा कि आज राजस्थान में एक ओर खेजड़ी बचाओ महापड़ाव चल रहा है, दूसरी ओर अरावली बचाने की जद्दोजहद है तो जैसलमेर से लोग राजधानी जयपुर के लिए ओरण बचाने पैदल निकले है। सरकार ने आज फिर मल्टीनेशनल कंपनियों को जमीन आवंटन करने की घोषणा की है यह राजस्थान के मुँह पर करारा तमाचा है। इतने गहरे असंतोष के बावजूद भाजपा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी को लेकर कोई स्पष्ट नीति अथवा कानून की घोषणा नहीं की है, यह बेहद निराशजनक है।

यूसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में अयाज सिद्दीकी का धमाल, पहला शतक उनके नाम

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। यूसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें दिन का पहला मुकाबला इस मैच में रॉयल पीएसएफ ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 19.3 ओवर में 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैवरिक्स की टीम की शुरुआत अयाज सिद्दीकी और नयाब संजयरी ने की। अयाज सिद्दीकी ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 48 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 11 छक्के लगाए। वहीं नयाब संजयरी ने 23 गेंदों में 29 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल रहे। मैवरिक्स की टीम ने 153 रन का लक्ष्य मात्र 11.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अयाज सिद्दीकी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यह शतक यूसीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला और सबसे तेज़ शतक रहा। मैवरिक्स टीम के ओनर सैयद काशिफ चिश्ती और मोहम्मद फैयाज ने टीम की शानदार जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके प्रदर्शन की सराहना की।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
Tel. No.: 01462-258665, 257509 E-mail Id: apbeaware gmail.com
क्रमांक/69 ए/2025-26/11507 दिनांक:-30/01/26
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भारत भूषण व्यास पुत्र श्री शंकर लाल व्यास निवासी गीता भवन के सामने ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित जायदाद आबादी मौहल्ला प्लॉट नं. 118 म्यु नं. 25 गली नं. 6 पोखरगंज ब्यावर क्षेत्रफल 209.03 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत् आवेदन किया है।
अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 15 दिवस के अन्दर अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

अजमेर-पुष्कर में फिल्मो की शूटिंग और पर्यटनो के विकास के लिए धरातल पर कोई घोषणा नही की गई

अजमेर। राजस्थान के आगामी बजट जो कि गुरूवार को विधान सभा में वित एवं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमार ने पुष्कर राज तीर्थ का महत्व और अजमेर के महत्वपूर्ण स्थलो को विशेष महत्व प्रदान नही किया गया है ।महासंघ के मुख्य संरक्षक कालीचरणदास खण्डेलवाल और संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि अजमेर-पुष्कर के विश्व स्तर के महत्व को बजट में ध्यान नही रखा गया है ।छोटे और मंझले व्यापारियो के परिवार की सुरक्षा,सामाजिक सुरक्षा,ग्रुप इन्श्योरेन्स,कोरोना काल के कर्जे माफ करने का प्रावधान नहीं किये जाने से व्यापारियो में नाराजगी व्याप्त है।

पशुपालकों के लिये बजट दिशाहीन, आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल, डेयरी क्षेत्र को झुनझुना, किसानों को ठोस राहत नहीं

बजट में पशुपालकों की अनदेखी, सरकार सपनों की खेती कर रही है : चौधरी

अजमेर,(हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पशुपालकों के लिए 'दिशाहीन, दिग्भ्रमित एवं आंकड़ों और शब्दों का मायाजाल' करार दिया है। चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में डेयरी एवं पशुपालकों को केवल झुनझुना पकड़ाया गया है, वास्तविक राहत का कोई प्रावधान नहीं किया गया। रामचंद्र चौधरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रदेश के पशुपालकों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 7 वर्ष पूर्व घोषित 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कम से कम 7 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'जब लागत आसमान छू रही है तो सहायता ज़मीन पर क्यों पड़ी है?' चौधरी ने यह भी कहा कि जिला दुग्ध संघों एवं आरसीडीएफ में कार्यरत लगभग 2500 ठेका श्रमिक, जो पिछले 15-20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें स्थायी करने का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया। अन्य विभागों की भांति संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा भी नहीं की गई और ना ही 2500 रिक्त पदों पर भर्ती की बात कही गई। उन्होंने कहा, 'जो लोग वर्षों से पसीना बहा रहे हैं, उनके भविष्य पर सरकार ने ताला लगा दिया है।' उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मिड-डे-मील योजना के तहत जिला संघों पर बकाया 300 करोड़ रुपये का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया ।इससे जिला दुग्ध संघ आर्थिक तंगी में फंसते जा रहे हैं। 'आर्थिक

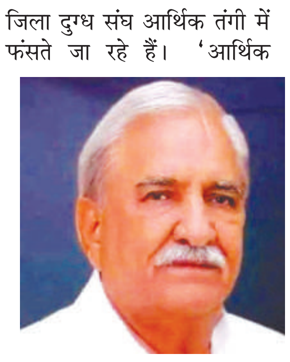

ऑक्सीजन के बिना संस्थाएं कैसे जीवित रहेंगी?' - चौधरी ने सवाल उठाया। रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सरस डेयरी क्षेत्र के पशुपालकों को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तर्ज पर डेयरी एवं पशुपालन को कृषि क्षेत्र घोषित किया जाएगा, लेकिन यह मांग भी अधूरी रह गई। बेसहारा पशुओं की समस्या के नियंत्रण के लिए भी कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया और न ही निःशुल्क सेक्स सॉर्टेड सीमन युद्ध स्तर पर देने की घोषणा की गई। उन्होंने सहकारी लोकतंत्र की अनदेखी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन दुग्ध समितियों एवं जिला संघों में चुनाव लंबित हैं, उनके समयबद्ध चुनाव कराने की कोई घोषणा नहीं की गई। 'लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी तो सहकार कैसे मजबूत होगा?' रामचंद्र चौधरी ने बजट में जिला संघों के लिए घोषित 2000 करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रावधान को 'मुंगेरी लाल के हसीन सपने' के समान बताया। उन्होंने याद दिलाया कि गत वर्ष भी 1000 करोड़ रुपये के रिफार्मिंग की घोषणा हुई थी, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। 'कागज़ी पुल बनाकर विकास नहीं होता' उन्होंने कहा। सरस ब्रांड के विस्तार के नाम पर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और हृष्टक्र में आउटलेट खोलने के लिए घोषित 100 करोड़ रुपये को भी चौधरी ने 'मृगतृष्णा' करार दिया और कहा कि जब प्रदेश के दुग्ध संघ आर्थिक संकट में हैं तो बाहरी विस्तार केवल दिखावा है। उन्होंने गंभीर चिंता जताई कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था, लेकिन सरकार की शिथिलता के कारण अब राज्य दूसरे स्थान पर खिसक गया है। पंचायत स्तर के पशु चिकित्सालयों में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया को उन्होंने 'ऊंट के मुंह में जीरा' बताया। अंत में रामचंद्र चौधरी ने कहा, 'यह बजट पशुपालकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अगर समय रहते सरकार ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कमजोर हो जाएगी।

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
क्रमांक / नियमन /25-26/2051 दिनांक 11/02/26
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति गरीमा टेलर पुत्री श्री पदम कुमार टेलर पत्नि श्री गजेन्द्र गोयल निवासी विद्या नगर, गणेशपुरा मार्ग, ब्यावर ने राजस्व ग्राम नयानगर के खसरा संख्या 1668 में स्थित नैना देव नगर के भूखण्ड संख्या 15 + अधिक भूमि कुल क्षेत्रफल 240.66 वर्गगज भूमि के आवासीय फी होल्ड पट्टा विलेख अधिक भूमि सहित प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः उक्त प्रकरण में अधिक भूमि की राशि राजकीय भूमि की दर से लिये जाने के आदेश प्रसारित है जिसके अनुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 15 अधिक भूमि कुल क्षेत्रफल 240.66 वर्गगज अधिक भूमि का आवासीय पट्टा विलेख दिया जाना है इस बाबत् किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
सीमायें (मौका रिपोर्ट के अनुसार)
पूर्व :- रोड 30 फीट पश्चिम :- प्लाट नं. 05
उत्तर :- प्लाट नं. 16 बी दक्षिण :- रोड 24 फीट
आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर
Tel. No.: 01462-258665, 257509 E-mail Id: apbeaware gmail.com
क्रमांक/69 ए/2025-26/10794 दिनांक:-07/01/26
आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धनराज खूबचन्दानी पुत्र स्व. श्री कैवलराम खूबचन्दानी निवासी नन्द नगर नं. 03 ब्यावर ने 69 ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नगर परिषद ब्यावर की सीमा में स्थित जायदाद आबादी मौहल्ला 1/6 नया नं. ईश्वरदास फतेहपुरिया मार्ग भवन सं. 01 ब्यावर क्षेत्रफल 107.11 वर्गमीटर का आवासीय पट्टा लेने बाबत् आवेदन किया है।
अतः उपरोक्त को आवासीय पट्टा विलेख जारी किये जाने के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के 15 दिवस के अन्दर अन्दर आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।
आयुक्त, नगर परिषद ब्यावर

सम्पादकीय...

बच्चा चोर का राष्ट्रीय नेटवर्क

देश भर में बच्चों के लापता होने के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई देश व्यापी नेटवर्क काम कर रहा है या फिर यह अलग-अलग राज्यों में होने वाली बिखरी हुई घटनाएं हैं। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण करें, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडवोकेट ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और अभियोजन से जुड़े आंकड़े सौंप दिए हैं लेकिन अभी भी एक दर्जन राज्यों में अब तक डाटा उपलब्ध नहीं कराया है उन्होंने कहा कि जब तक सभी राज्यों से पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है।

बच्चों की गुमशुदगी के बढ़ते मामलों के पीछे अलग-अलग सोच है एक लाइन यह है कि इन बच्चों को भीख मांगने के लिए उठाया जाता है फिर अपंग करके उनसे भीख मंगाई जाती है। एक सच यह है कि मानव तस्करी के रूप में गुमशुदा बच्चों को इधर-उधर किया जाता है एक सोच यह है कि बच्चे खुद घर से भाग रहे हैं जबकि एक सच यह है कि इन बच्चों को सोने तरीके से उठाकर उनके अंग निकाल उनका बड़ा व्यापार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अपनी फैसले के पीछे यही सोच रहा है कि आखिर यह सारा काम सुनियोजीत तरीके से तो नहीं हो रहा है।

मौजूदा समय में लापता हुए बच्चे की बरामदगी आसान है क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरा नेटवर्क चलता है पुलिस के पास पूरा डाटा और फोटो रहते हैं संदेहसपद दिखने वाले बच्चों को तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और समाज में जागरूकता भी आ गई है कि बच्चों का शोषण होते कोई नहीं देखना चाहता। मजेदार बात तो यह है कि इतने बच्चे लापता होते हैं वह जाते कहां है उन्हें जमीन निकल जाती है या आसमान उड़ा ले जाता है। किसी राज्य से निकला बच्चा देश के किसी हिस्से में तो मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ बड़ा मामला है सरकार को इसके लिए बड़े कदम उठाने चाहिए एक सुझाव यह भी है कि इनका राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल बने ताकि फोटो नाम पते के आधार पर बच्चों को तत्काल ढूंढा जा सके।

वैभव लोढ़ा...

इतिहास में आज

2013: उत्तर कोरिया ने तीसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
2009: भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया।
1999: बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू।
1975: भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया।
1928: गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की।

-धर्म चंद मेहता

क्रॉस फायर

❑लोक सभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश।
◆पास हो या ना हो पर गलत पेश नहीं किया।
❑अविश्वास प्रस्ताव पर बहस तक ओम बिरला लोकसभा में नहीं जाएंगे।
◆जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे।
❑पेंगुइन का दावा भारत के सेनाध्यक्ष नरवडे की किताब पब्लिश नहीं हुई।
◆फिर भगवान ने छाप कर भेज दी क्या।
❑राहुल गांधी बोले या तो किताब छापने वाली कंपनी झूठ बोल रही है या सेनाध्यक्ष नरवणे।
◆झूठ को मानेगा कौन।
❑ए आई और डीपफेक पर सरकार का बड़ा एक्शन, नए नियम बनाए।
◆रोक सके तो जाने।
❑रूस के विदेश मंत्री बोले भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का भारी दबाव।
◆दुख की बात तो यह भारत दबाव में आ गया।
❑प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भाजपा के बजट को आंकड़ों का मायाजाल बताया।
◆जनता भी समझती है मूर्ख बना रहे हैं।
❑राज्य बजट आज विकसित राजस्थान के संकल्प को लेकर होगी कई बड़ी घोषणाएं।
◆मतलब झुनझुना खूब बजेगा।

.............अंजू लोढ़ा

आज का राशिफल

गुरूवार 12 फरवरी, 2026

मेष राशि: कार्यस्थल पर आप शानदार प्रदर्शन करेंगे और उत्साह के साथ काम करेंगे। यदि आप परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप सफल होंगे।

वृषभ राशि: आज आप कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे। यदि व्यवसाय या नौकरी की तलाश में हैं तो आप सफल रहेंगे। नौकरीपेशा जातकों के लिए पदोन्नति या प्रगति के प्रबल संकेत हैं।

मिथुन राशि: रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या खेल से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। कुछ अतिरिक्त प्रयास द्वारा पुराने ऋण प्राप्त हो सकते हैं।

कर्क राशि: आर्थिक रूप से दिन शुभ है। आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और आप कठिन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। प्रतिद्वंद्वी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।

सिंह राशि: बौद्धिक गतिविधियों के लिए यह एक अच्छा दिन है। आप सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति करेंगे। इच्छित काम भी पूरा हो सकता है। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को वांछित परिणाम मिलेंगे।

कन्या राशि: आज परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। आप अनावश्यक काम में शामिल होंगे और कठिनाइयों का सामना भी करेंगे।

तुला राशि: कार्यस्थल पर किए गए प्रयास आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। मेहनती जातकों के लिए नौकरी में पदोन्नति और व्यवसाय में प्रगति संभव है।

वृश्चिक राशि: आपको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। यदि आप उनमें से अधिकांश का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो आप सदैव के लिए वह अवसर खो देंगें।

धनु राशि: आज का दिन खुशियां लेकर आएगा और आपको जोश से भर देगा। आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ स्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से आप अधिक सुरक्षित रहेंगे।

मकर राशि: आर्थिक रूप से यह दिन बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी, वाहन आदि में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। आपके करियर में कुछ बदलाव होंगे और यह फायदेमंद भी साबित होंगें।

कुम्भ राशि: आज भाग्य आपका साथ देगा। कठिनाइयां समाप्त होंगी और रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। वित्तीय मामलों में आपके लिए व्यवस्थित काम करना फायदेमंद और लाभकारी होगा।

मीन राशि: आज परिणाम आपके पक्ष में होंगे। काम में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है। अपने छिपे हुए दुश्मनों से सावधान रहें, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं।

राजेन्द्र गुप्ता
ज्योतिषी और हस्तरेखाविद, मो. 9611312076

नोट- अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके या इसी व्हाट्स एप नम्बर पर मैसेज भेजकर पहले शर्तें जान लेवें, इसी के बाद अपनी बर्थ डिटेल और हैंडप्रिंट्स भेजें।

डिजिटल क्रांति पर साइबर प्रहार गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

डिजिटल युग ने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं ने लेन-देन को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया है। आज एक सामान्य नागरिक भी कुछ सेकंड में देश के किसी भी कोने में धन भेज सकता है, बिल जमा कर सकता है या निवेश कर सकता है। यही डिजिटल क्रांति 'नए भारत' और 'विकसित भारत' की आधारशिला मानी जा रही है।

किंतु इसी क्रांति के साथ एक गहरी विडंबना भी उभरकर सामने आई है-डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर लूट की भयावह बढ़ोतरी। हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की घटनाएँ न केवल आमजन को आर्थिक रूप से आहत कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। डिजिटल व्यवस्था की मूल आत्मा 'विश्वास' है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन पर उभरे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो वह केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उस संपूर्ण तंत्र पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित लेन-देन का आश्वासन देता है। किंतु जब यही विश्वास ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, निवेश घोटालों और पहचान चोरी के कारण टूटने लगता है, तब डिजिटल विकास की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में नकली नोटों की भरमार हो जाए तो मुद्रा पर विश्वास डगमगा जाता है, उसी प्रकार यदि डिजिटल लेन-देन में ठगी सामान्य अनुभव बन जाए, तो नागरिक डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाने लगते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत हानि का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के लिए भी खतरे की घंटी है। परंपरागत अपराधों और डिजिटल अपराधों की तुलना करें तो दोनों के स्वरूप और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। पहले चोरी या डकैती किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती थी, अपराधी की पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट होती थी और जांच प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी। डिजिटल अपराधों में अपराधी अदृश्य है, वह किसी दूसरे राज्य या देश में बैठकर वारदात कर सकता है, और कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों को निशाना बना सकता है। पारंपरिक अपराध में जोखिम अपराधी के लिए अधिक था, डिजिटल अपराध में जोखिम कम और लाभ अधिक है। यही असंतुलन इसे अत्यंत खतरनाक बनाता है। एक अन्य तुलनात्मक पक्ष यह है कि डिजिटल अपराधों में पीड़ित की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी अलग होती है। ठगी का शिकार व्यक्ति स्वयं को अपराधी के सामने असहाय पाता है। पुलिस और साइबर क्राइम कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे तकनीकी कारणों का हवाला देकर लौटा दिया जाता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास जन्म लेता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल है, समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, और समय पर कार्रवाई न होने से धन की रिकवरी असंभव हो जाती है। इससे यह धारणा बनती है कि डिजिटल अपराध का कोई वास्तविक दंड नहीं है। सरकार और न्यायपालिका ने समय-समय पर इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है। शीर्ष अदालत द्वारा

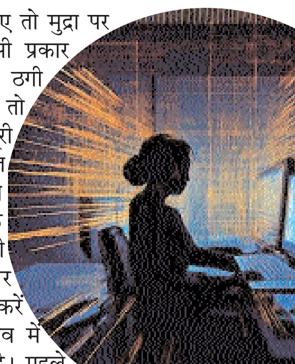

ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखना इस बात का संकेत है कि यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक आक्रमण भी हो सकता है। किंतु नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। अनेक प्लेटफार्म और हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी स्पष्ट दिखती है। यदि शिकायत के बाद प्रारंभिक 'गोल्डन ऑवर' में ही बैंक खाते फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रैक करने की प्रभावी व्यवस्था न हो, तो बाद की प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह जाती है। वित्तीय प्रणाली की दृष्टि से देखें तो डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना निवेश, उपभोग और बैंकिंग व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आमजन को यह आशंका सताने लगे कि ऑनलाइन निवेश योजनाएँ या भुगतान सुरक्षित नहीं हैं, तो वह नकद लेन-देन की ओर लौट सकता है। यह प्रवृत्ति सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की नीति को कमजोर करेगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों के लिए भी यह संकेत नकारात्मक हो सकता है कि साइबर सुरक्षा का ढांचा पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है। अतः यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का भी केंद्रीय प्रश्न है। समाधान के स्तर पर तुलनात्मक रूप से देखें तो विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखा है। वहाँ विशेषीकृत एजेंसियाँ, उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ, त्वरित डेटा साझा करने की प्रणाली और सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं। भारत में भी साइबर क्राइम ब्यूरो और डिजिटल सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, परंतु उनकी क्षमता, संसाधन और प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस बल को केवल पारंपरिक अपराधों की नहीं, बल्कि डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण की भी विशेषज्ञता दी जानी चाहिए। जब तक जांच एजेंसियाँ तकनीकी रूप से अपराधियों से एक कदम आगे नहीं होंगी, तब तक रोकथाम कठिन रहेगी। एक महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक जागरूकता का भी है। तकनीक जितनी उन्नत होती है, अपराधी भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। अतः केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि लोग संदिग्ध लिंक, कॉल और निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि जागरूकता का दायित्व पीड़ित पर डालकर व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती।

सुरक्षा का मूल दायित्व तंत्र का है, नागरिक का नहीं। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी इस समस्या को जटिल बनाते हैं। यदि बैंक या भुगतान प्लेटफार्म समय पर कार्रवाई नहीं करते, या आंतरिक मिलीभगत से फर्जी खाते संचालित होते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली, जवाबदेही और कठोर दंड अनिवार्य हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों की केवाईसी प्रक्रिया को अधिक कठोर और वास्तविक बनाना होगा, ताकि फर्जी पहचान के माध्यम से खाते खोलना कठिन हो। अंततः डिजिटल क्रांति का उद्देश्य सुविधा, पारदर्शिता और समृद्धि है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसका नैतिक औचित्य कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, और न ही यह वांछनीय है। किंतु इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना अनिवार्य है। सरकार को नीति, तकनीक और प्रशासन-तीनों स्तरों पर समन्वित रणनीति अपनानी होगी। साइबर अपराध के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को समयबद्ध राहत, जांच एजेंसियों का सशक्तीकरण और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही-ये सब मिलकर ही धोखाधड़ी मुक्त डिजिटल परिवेश का निर्माण कर सकते हैं।

योगी के बजट से 2027 की बिसात, आंकड़ों के सहारे सियासी दांव

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट केवल अगले वित्त वर्ष की आय-व्यय योजना नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की सबसे ठोस राजनीतिक पटकथा के रूप में देखा जा रहा है। 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के इस बजट के जरिए सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव से पहले विकास, सुरक्षा और कल्याण तीनों मोर्चों पर अपने दावों को आंकड़ों के साथ जमीन पर उतारकर पेश करना चाहती है।

पिछले बजट के मुकाबले करीब 12.9 प्रतिशत बढ़े इस आकार को सत्ता पक्ष 'विश्वास का बजट' बता रहा है, जबकि इसके भीतर छिपा राजनीतिक संदेश यह है कि सरकार न तो संसाधनों की कमी से जूझ रही है और न ही चुनाव से पहले खर्च बढ़ाने से पीछे हट रही है। सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपने मजबूत पक्ष के रूप में सामने रखा है। 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार 30.25 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर यह दिखाने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या वाला राज्य नहीं, बल्कि तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बन चुका है। 2016-17 में जहां जीएसडीपी करीब 12.75 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं आठ-नौ वर्षों में इसके ढाई गुना से अधिक होने को सरकार स्थिर शासन और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा बता रही है। 2027 के चुनाव में यह आंकड़ा खासतौर पर शहरी मतदाताओं, कारोबारियों और निवेश से जुड़े वर्गों के सामने रखा जाएगा, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बदलाव विकास की रफ्तार को रोक सकता है। प्रति व्यक्ति आय को लेकर दिए गए आंकड़े भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं। 2016-17 में 54,564 रुपये रही प्रति व्यक्ति आय के 2024-25 में बढ़कर 1,09,844 रुपये होने और 2025-26 में इसके 1,20,000 रुपये तक पहुंचने के अनुमान को सरकार आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर पेश कर रही है। यह संदेश खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, जो महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य खर्च को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। सरकार का दावा है कि आय बढ़ने का मतलब सिर्फ आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि उपभोग और जीवन स्तर में बदलाव है। गरीबी के मोर्चे पर 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का दावा 2027 के लिहाज से सबसे बड़ा सामाजिक कार्ड माना जा रहा है। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत कार्ड, शौचालय और बिजली कनेक्शन जैसी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को एक साथ रखकर सरकार यह दिखाना चाहती है कि गरीब सिर्फ योजनाओं का नाम नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति का केंद्र है। चुनावी रणनीति में यह वर्ग इसलिए अहम है क्योंकि यह सीधे सरकार से जुड़ाव महसूस करता है और उसके फैसले अक्सर स्थिर रहते हैं। रोजगार को लेकर बजट में पेश किए गए आंकड़े विपक्ष के सबसे मजबूत मुद्दे का जवाब माने जा रहे हैं। बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत बताकर सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में रोजगार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। पुलिस विभाग में 2017 से अब तक 2 लाख 19 हजार से अधिक भर्तियां, 1 लाख 58 हजार पदोन्नतियां, 60 हजार से ज्यादा प्रशिक्षणाधीन जवान और 83 हजार से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर सरकार यह दिखाना चाहती है कि सरकारी नौकरियां सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहीं। शिक्षा क्षेत्र में 34 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी इसी दिशा में रखा गया कदम है, क्योंकि शिक्षक समुदाय ग्रामीण और कस्बाई राजनीति में राय बनाने की अहम भूमिका निभाता है। युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की रणनीति भी बजट में साफ दिखती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण देकर हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका राजनीतिक मतलब यह है कि सरकार उन युवाओं को भी साधना चाहती है, जिन्हें सरकारी नौकरी की सीमित सीटों से निराशा हुई है।

अगर यह योजना आंशिक रूप से भी सफल होती है, तो 2027 तक लाखों परिवार सीधे इससे जुड़ सकते हैं। कृषि क्षेत्र के आंकड़े ग्रामीण राजनीति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। 3 लाख 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र में सरकार का सबसे मजबूत चुनावी हथियार माना जा रहा है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से करीब 3000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लाभ का दावा किसानों को यह याद दिलाने के लिए है कि भुगतान सीधे खाते में पहुंचा है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की लाखों मीट्रिक टन खरीद और हजारों करोड़ रुपये के भुगतान के आंकड़े न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश हैं। नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था ग्रामीण मतदाताओं के लिए सीधा संदेश है कि सिंचाई लागत सरकार उठाने को तैयार है। महिलाओं को लेकर बजट में दिए गए आंकड़े 2022 के चुनावी अनुभव से निकले हुए माने जा रहे हैं, जहां महिला मतदाताओं का झुकाव निर्णायक साबित हुआ था। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत 26.81 लाख बालिकाओं को लाभ, सेफ सिटी परियोजना, महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और वर्किंग वूमेन हॉस्टल जैसे प्रावधान यह दिखाते हैं कि सरकार महिला सुरक्षा और सम्मान को केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा मानती है। महिला मतदाता भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर निर्णय करती हैं, और बजट में यह संदेश उसी दिशा में जाता है। कानून-व्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी 2027 की चुनावी कहानी का अहम हिस्सा हैं।

डकैती, लूट, हत्या और अपहरण जैसे अपराधों में 40 से 80 प्रतिशत तक कमी के दावे के जरिए सरकार यह स्थापित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा असुरक्षित नहीं है। पुलिस भवनों, आवास और संसाधनों पर हजारों करोड़ रुपये के प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। यह संदेश शहरी मतदाताओं, व्यापारियों और महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम है। कुल मिलाकर 2026-27 का बजट एक ऐसा दस्तावेज बनकर सामने आया है, जिसमें हर बड़ा आंकड़ा 2027 के मतदाता को ध्यान में रखकर चुना गया है। विकास, कल्याण, सुरक्षा और पहचान चारों को जोड़कर सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सत्ता की निरंतरता ही स्थिरता की गारंटी है। आने वाले महीनों में यही बजट गांव-गांव, शहर-शहर होने वाली राजनीतिक बहसों का आधार बनेगा, जहां सरकार इन आंकड़ों के सहारे भरोसा मांगेगी और विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को चुनौती देने की कोशिश करेगा।

महान चिंतक, समाज-सुधारक और देशभक्त स्वामी दयानन्द सरस्वती

बाल मुकुन्द ओझा

उन्नीसवीं शताब्दी के महान समाज-सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रध्दा के साथ लिया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, महान चिंतक, समाज-सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड और मूर्ति-पूजा का बोल-बाला था। स्वामी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1876 में हरिव्दार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखण्डखंडिनी पताका फहराकर पोंगा-पंथियों को चुनौती दी। उन्होंने फिर से वेद की महिमा की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे। हिंदू पंचांग के अनुसार, स्वामी दयानंद सरवती का जन्म फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को होता है। स्वामी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है। उन्होंने अपने समय में समाज में फैली बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति न केवल समाज को जागरूक किया बल्कि इन्हें दूर करने में भी काफी योगदान दिया। अपने परिवार से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद, वह एक महान वैदिक विद्वान के रूप में उभरे। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ज्ञान और सत्य की खोज में भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले गए। स्वामी दयानंद अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्रहित के उत्थान, समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी ओजस्वी विचारों से समाज में नव चेतना का संचार जागृत किया। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों का प्रमाण देते हुए समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने सन् 1874 में अपने कालजयी ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश' की रचना की। वर्ष 1908 में इस ग्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कुल मिलाकर उन्होंने 60 पुस्तकें, 14 संग्रह, 6 वेदांग, अष्टाध्यायी टीका, अनके लेख लिखे जिनमें 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका', 'संस्कार-विधि', आर्याभिविनय आदि अनेक विशिष्ट ग्रन्थों की रचना की। अपने 59 वर्ष के जीवन में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लोगो को जगाया और अपने ज्ञान प्रकाश को देश में फैलाया। उन्होंने अपने कार्यो से समाज को नयी दिशा एवं उर्जा दी। महात्मा गाँधी जैसे कई महापुरुष स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेदों की महत्ता के बारे में समझाया। दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। जिससे अँग्रेजी सरकार स्वामी दयानंद से बुरी तरह तिलमिला गयी और स्वामीजी से छुटकारा पाने के लिए, उन्हें समाप्त करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रचे। 1857 की क्रांति में भी स्वामी जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लोहा लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे उन्होंने राष्ट्र में व्याप्त कुरीतियों एवम अन्धविश्वासो का सदैव विरोध किया । उन्होंने ही सबसे पहले वर्ष 1876 में 'स्वराज' का नारा दिया जिसे बाद में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी ने आगे बढ़ाया। दयानन्द सरस्वती जी ने विधवा नारियों के पुनर्विवाह के लिये अपना मत दिया और लोगो को इस ओर जागरूक किया। स्वामी जी ने सदैव नारी शक्ति का समर्थन किया उनका मानना था कि नारी शिक्षा ही समाज का विकास हैं। पति के साथ पत्नी को भी उसकी मृत्यु शैया पर अग्नि को समर्पित कर सती करने की अमानवीय सतीप्रथा का भी उन्होने विरोध किया। उन्होंने नारी को समाज का आधार कहा और कहा उनका शिक्षित होना जरुरी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश' मूल रूप में हिन्दी भाषा में लिखा गया।

जनरल नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा और दिल्ली पुलिस की जांच

- महेन्द्र तिवारी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की पीडीएफ कॉपी के सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रसार को लेकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। यह मामला किसी अपराध या घोटाले से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मकथा से संबंधित है जो अभी औपचारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई और फिर भी व्यापक रूप से पढ़ी जा रही है।

पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की डिजिटल प्रति अचानक विभिन्न संदेश माध्यमों और सामाजिक मंचों पर फैल गई। देखते ही देखते यह रचना केवल सैन्य इतिहास की किताब न रहकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। प्रश्न यह नहीं रह गया कि पुस्तक लीक कैसे हुई, बल्कि यह बन गया कि वह अब तक प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी। यह आत्मकथा चार दशकों से अधिक लंबे सैन्य जीवन का विवरण देती है। एक युवा अधिकारी के रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती से लेकर देश की थलसेना के सर्वोच्च पद तक की यात्रा इसमें दर्ज है। इसमें पूर्वी सीमा पर हुए टकराव, पश्चिमी मोर्चे पर तनाव, पड़ोसी देशों के साथ संघर्षविराम, और एक भीषण वैश्विक महामारी के दौरान सेना की भूमिका जैसे प्रसंग शामिल हैं। ऐसे समय में जब देश का सैन्य इतिहास अक्सर आधिकारिक वक्तव्यों और संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित रह जाता है, यह पुस्तक घटनाओं के भीतर झांकने का अवसर देती है। शायद यही कारण है कि इसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। प्रकाशन की प्रक्रिया सामान्य नहीं रही। पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, अग्रिम आदेश भी लिए गए, परंतु अचानक सब कुछ रोक दिया गया। पाठकों को धन वापस कर दिया गया और कहा गया कि आवश्यक स्वीकृतियां लंबित हैं। पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा लिखी जाने वाली स्मृतियों के लिए रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, यह कोई नई बात नहीं है। परंतु जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों से यह सामने आया कि उसी अवधि में दर्जनों अन्य पुस्तकों को अनुमति मिल चुकी है और केवल यही एक रचना अटकी हुई है, तो संदेह स्वाभाविक हो जाता है। लेखक स्वयं कई अवसरों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था और उसे प्रकाशक को सौंप दिया था। अनुमति प्राप्त करना उनका दायित्व नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुस्तक की सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई है और उसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी नहीं है। यही नहीं, पुस्तक के मसौदे को पहले ही कई वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने पढ़ा था और उसकी सराहना भी की थी। इन प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलता है कि सामग्री न तो मनगढ़ंत है और न ही हल्की। इसके बावजूद पुस्तक पर चुप्पी बनी रही। इस बीच कुछ समाचार माध्यमों ने इसके अंशों के आधार पर लेख प्रकाशित किए। उन लेखों में सीमा पर हुए संकटों के दौरान लिए गए राजनीतिक और सैन्य निर्णयों का उल्लेख था। संसद में जब इन संदर्भों का उपयोग करने की कोशिश की गई तो भारी हंगामा हुआ और चर्चा रोक दी गई। इसके तुरंत बाद वही डिजिटल प्रति, जिसे अब तक केवल सीमित लोगों ने देखा था, व्यापक रूप से फैलने लगी। यह एक अजीब स्थिति थी, जिसमें एक पुस्तक आधिकारिक रूप से अस्तित्वहीन मानी जा रही थी, परंतु वास्तविकता में हजारों पाठकों तक पहुंच चुकी थी। अब जांच का केंद्र यह है कि इस अनधिकृत प्रसार के लिए कौन जिम्मेदार है। कानून की दृष्टि से यह कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि अप्रकाशित सामग्री को बिना अनुमति साझा किया गया। यदि यह माना जाए कि पुस्तक में संवेदनशील सैन्य जानकारियां हैं, तो उस पर गोपनीयता से जुड़े कानून भी लागू हो सकते हैं। परंतु यहां एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या जांच का उद्देश्य वास्तव में कानून का पालन कराना है या फिर उन तथ्यों को नियंत्रित करना है जो असुविधाजनक साबित हो सकते हैं। इस आत्मकथा में जिन घटनाओं का उल्लेख है, वे हाल के वर्षों की सबसे संवेदनशील राष्ट्रीय घटनाओं में से हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में हुई झड़पों में देश ने अपने जवान खोए, परंतु उन घटनाओं के बारे में आधिकारिक विवरण सीमित रहा। सरकार की ओर से एक विशेष प्रकार का आख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें दृढ़ता और सफलता पर जोर था। यदि किसी पूर्व थलसेना प्रमुख की पुस्तक उस आख्यान से अलग तस्वीर पेश करती है, तो स्वाभाविक है कि वह राजनीतिक रूप से असहज कर सकती है।

बजट में केकडी क्षेत्र को सड़क, पुल, जल संसाधन व प्रशासनिक ढांचे के लिए करोड़ों की घोषणा

केकड़ी (हुक्मनामा समाचार)। उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में सत्र 2026-27 के प्रस्तुत किये बजट में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ किसानों महिलाओ युवाओ व पेंशनर्स सभी वर्गों को सौगाते दी साथ ही विधायक शत्रुघ्न गोतम के प्रयासों से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को उल्लेखनीय विकास सौगातें मिली हैं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के सतत प्रयासों के चलते क्षेत्र को आधारभूत ढांचे, सड़क कनेक्टिविटी, जल संसाधन, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण एवं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।जिनमें मिनी सचिवालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी और लोगों को राहत मिलेगी।इस हेतु विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राज्य सरकार एवं उपमुख्यमंत्री (वित्त) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट 2026-27 केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और आमजन को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। कृषि के लिए जल संसाधनों को मिलेगा संबल-: कृषि प्रधान क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण एवं सिंचाई सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई हैमदन सरोवर, धानवा बांध एवं संबंधित नहरों की मरम्मत व जीर्णोद्धार (सरवाड़) के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति, जिससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभमिलेगा और सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी।केकडी बिजयनगर सड़क व मेहरुकला सड़क से लोगो को भारी राहत मिलेगी ऐतिहासिक सरवाड़ किले के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्वरोजगार के लिए आवेदनों में 15 तक कर सकेंगे आक्षेपपूर्ति

बारां (हुक्मनामा समाचार)। अनुजा निगम के माध्यम से राष्ट्रीय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वच्छकार और विकलांग आदि को स्वरोजगार दिलाने के लिए ऑनलाइन प्राप्त किए गए ऋण आवेदनों के लिए साक्षात्कार फरवरी माह के अन्त तक करवाया जाना प्रस्तावित है। निगम के परियोजना प्रबंधक शुभम नागर ने बताया कि आवेदनों की जांच पर जिन आशार्थियों के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए हैं उनके आवेदनों को आक्षेप में डाला गया है।

डोल मेला भूमि सीमाज्ञान प्रकरण में जिला कलेक्टर ने नाम सौंपा ज्ञापन

नाहरगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। नाहरगढ़ कस्बे में विगत डेढ़ वर्ष से चल रहे डोल मेला भूमि के सीमाज्ञान और अतिक्रमण हटाने के मामले में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर 5 दिवस में निराकरण नहीं होने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। इस मामले को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में कस्बे के सर्व समाज के लोग उपतहसील कार्यालय पहुँचे। और कार्यालय के द्वार पर बैठ कर नारेबाजी करते हुए करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। और नायब तहसीलदार शिवप्रकाश टाटू को जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंप कर 5 दिन में सीमज्ञान नहीं होने पर नाहरगढ़ चौराहे पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। ज्ञापन में कस्बेवासियों द्वारा पूर्व में डोल एकादशी 2024 में देवविमानो को पूजन स्थल रोक कर किये प्रदर्शन के बाद एसडीएम द्वारा की गई अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की घटना का उल्लेख किया। वही ज्ञापन में उल्लेख कर बताया कि 6 माह पूर्व भी जलझूलनी एकादशी 2025 के दिन देव विमानों को रोकने की चेतावनी के बाद प्रशासन द्वारा 20 दिन के अंदर सेटलमेंट विभाग से सीमाज्ञान करवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाने का आश्वासन दिया था। जिसके बावजूद 6 माह बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली।

कई बार सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर अवगत करवाया। परंतु सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। जिसके बाद बुधवार को सर्व समाज के द्वारा रोष जताते हुए 5 दिन का अल्टीमेटम देकर चक्का जाम करने की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कस्बेवासी उपस्थित रहे।

स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति :राज्यपाल

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि युवा स्वयं के विकास के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। उन्होंने स्काउट गाइड संगठन के युवाओं को दृढ़ संकल्प शक्ति और मन बनाकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को अधिकारों की बजाय राष्ट्र और समाज तथा शिक्षा के प्रति कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बागडे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति से जुड़ा संगठन है। उन्होंने राजस्थान को योद्धाओं की भूमि बताते हुए कहा कि यहां का व्यक्ति शौर्य, वीरता और साहस से जुड़ा है। यहां निरंतर लड़ाइयाँ हुई पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण की भावना रही है। उन्होंने सेना में यहां के सर्वाधिक युवाओं के होने की चर्चा करते हुए स्काउट गाइड से जुड़े युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने आपात काल में स्काउट गाइड की रही भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वह स्वयं स्काउट संगठन में रहे हैं। यह अनुशासन से जुड़ा युवाओं को प्रेरणा देने वाला संगठन है। समारोह में विधायक दर्शन सिंह और वीरेंद्र सिंह, अखिल शुक्ला ने भी विचार रखें। स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने राजस्थान में संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले राज्यपाल ने श्रेष्ठ स्काउट गाइड को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। स्काउट गाइड ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के साथ साहसिक कैंप आदि से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

जेठाना में मनरेगा बचाओ महासंग्राम जागरण चौपाल का हुआ आयोजन

मांगलियावास (हुक्मनामा समाचार)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम' अभियान के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत जेठाना में आयोजित जन जागरण चौपाल में सम्मिलित होकर जनसंवाद किया। मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मज़बूत बुनियाद है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की जनविरोधी नीतियों और बजट कटौती के कारण आज यह योजना संकट में है, जिससे हमारे गरीब मज़दूर भाइयों-बहनों का हक छीना जा रहा है।इस अवसर पर पीसांगन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश चौहान जी, कांग्रेस सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष मुरली जी वैष्णव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रदीप जी कुमावत, स्ट जिला सचिव मूलचंद जी, महासंगठन मंत्री सगीर अहमद जी, प्रेम जी गुर्जर, वार्ड मेम्बर अनिल कुमार जी सहित समस्त सम्मानित कांग्रेस पदाधिकारी, देवतुल्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण साथी उपस्थित रहे।

जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल के मामलों का मौके पर पहुंचकर कराया निस्तारण

बारां (हुक्मनामा समाचार)। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बुधवार को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्रकरणों के सत्यापन व निस्तारण के संबंध में अंता क्षेत्र के बिजौरा, बमूलियाकलां व बड़वा में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए समस्या समाधान के निर्देश प्रदान किए।

बिजौरा निवासी पवन की शिकायत थी कि उनकी ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से भुगतान नहीं हुआ है। जिला कलक्टर द्वारा मौके पर सत्यापन करने पर परिवादी ने मौखित एवं लिखित बताया गया कि उसे गत जनवरी माह तक का भुगतान कर दिया गया है और वह कार्यवाही से संतुष्ट है। जिला कलक्टर ने ग्राम पंचायत बिजौरा के सफाई ठेकेदार को सफाई कर्मचारियों को सफाई करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने एवं सफाई कर्मचारियों के एसआई एवं पीएफ काटने के निर्देश दिए। यह मामला ठेकेदार एवं उसके श्रमिकों के मध्य का निजी मामला था। फिर भी प्रशासन द्वारा प्रकरण का निस्तारण करवा दिया गया। बमुलिया कलां निवासी परिवादी विनोद ने शिकायत में बताया गया था कि गांव में सुमित्रा सुमन पत्नी डालचंद सुमन द्वारा शौचालय का पानी सड़क पर छोड़ा जा रहा है। इस कारण आमजन को आवागमन में काफी समस्या हो रही है। इसका कारण इनके आगे के दो घरो के द्वारा सार्वजनिक नाली को बंद किया हुआ है इससे ये मकान वाले भी अपने मकान का गन्दा पानी रोड पर छोड़ रहे है। जिला कलक्टर ने शिकायत का सत्यापन करते हुए सुमित्रा सुमन के मकान के शौचालय का पानी की निकासी के लिए सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को समस्या का सम्पूर्ण समाधान करने के निर्देश प्रदान किए। जिस पर कार्यवाही करते हुए पानी की निकासी के लिए पाइप लगवाकर पानी की निकासी सही तरीके से करवा दी गई है।

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लाइव बजट प्रसारण सुना

चित्तौड़गढ (हुक्मनामा समाचार)।राज्य सरकार के बजट 2026 के लाइव प्रसारण को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा DOIT (Department of Information Technology & Communication) कार्यालय में सामूहिक रूप से सुना गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (भू-अभिलेख) रामचंद्र खटीक, कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला, छ्ह्ढ्ढ्ड्ड के संयुक्त निदेशक, उप निदेशक सहित विभाग के कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने बजट में जिले के विकास, ई-गवर्नेंस, आईटी सेवाओं, ग्रामीण कनेक्टिविटी तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी घोषणाओं को गंभीरता से सुना और बजट की प्रमुख बातों पर चर्चा भी की।

हज पर जाने वाले हाजियों के लिए मेडिकल टीकाकरण कैंप व प्रशिक्षण शिविर किया आयोजित

नागौर (हुक्मनामा समाचार)। की दरगाह सूफी हमीदुद्दीन ग्रीन हाउस गार्डन में 2026 हज पर जाने वाले हाजियों के लिए मेडिकल टीकाकरण कैंप व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया तबरेज खान ने बताया कि पूरे नागौर जिले में 544 हाजियों को टीका लगाया जेसे की डीडवाना में 34 मकराना में 89, वह नागौर में 62 शेरानी बाद मे 42, वह गांव बासनी में 317, व पूरे नागौर जिले से तीन हज इंस्पेक्टर जोकि हाजियों के साथ राजस्थान सरकार की तरफ से मक्का मदीना उनकी खिदमत करने के लिए उनके साथ जाएंगे ।

आज जिले का लास्ट कैंप आयोजित किया गया दरगाह सूफी हमीदुद्दीन के सदर हाजी शमशेर खान ने बताया कि नागौर जिले के सभी हाजियों टीके आज लग गए हैं दरगाह शरीफ के ग्रीन हाउस गार्डन में पूरा इंतजाम टेंट व सभी हाजियों के लिए खाने का इंतजाम दरगाह कमेटी की तरफ से किया गया अब आगे की प्रक्रिया यह रहेगी सभी हाजियों की अब तीसरी किस्त जमा करने की तारीख बहुत जल्द आने वाली है आज इस मौके पर मदरसा के सदर सदाकत सुलेमानी राजस्थान सरकार के पूर्व जिला संयोजक मोइनुद्दीन शेख राजस्थान सरकार के नागौर जिला हज ट्रेनर रमजान खान राजस्थान सरकार के नागौर जिला हज ट्रेनर प्यार मोहम्मद खान जयपुर जिला हज ट्रेनर अब्दुल हकीम शहर काजी मेहराज ऊसमानी शौकत गोरी दिल फराज खान कांग्रेस जिला महासचिव जावेद गोरी महबूब खान समाजसेवी उमर सोनी सगीर आलम अंसारी इलियास गोरी नदीम खान कमल हसन आरिफ गोरी वार्ड पार्षद मोहम्मद अली वार्ड पार्षद मोहम्मद कासम वह कहीं सहयोगी कार्यकर्ता व समाजसेवी मौजूद रहे

बोर्ड परीक्षाएं आज से प्रारम्भ- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विद्यार्थियों को शुभकामनाएं

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित सीबीएसई, आईसीएसई तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि परीक्षा जीवन की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, इसलिए विद्यार्थी तनावमुक्त होकर पूरे परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता के साथ परीक्षा दें। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करने से अवश्य ही सफलता मिलती है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को प्रोत्साहित करें और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें, ताकि विद्यार्थी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी स्तरों पर परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। साथ ही, अन्य बोर्डों, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों एवं कक्षा 8वीं, 5वीं तथा राज्य स्तरीय समान परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर आयोजित होंगी।

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024,पात्रता जांच हेतु अंग्रेजी विषय की विचारित सूची जारी

अजमेर (हुक्मनामा समाचार)। ।राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के तहत अंग्रेजी विषय के पदों हेतु पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी की गई है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आयोग सचिव ने बताया कि उक्त विषय के पदों हेतु प्रश्न पत्र-प्रथम सामान्य ज्ञान की परीक्षा 11 सितंबर तथा प्रश्न पत्र-द्वितीय अंग्रेजी की परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर 2025 को किया गया था। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवानियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त 757 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु विचारित सूची में सम्मिलित किया गया है। विचारित सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन/वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कृषि ऋण शिविर कल

बारां (हुक्मनामा समाचार)। किसानों को सुलभ एवं त्वरित ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 13 फरवरी को मांगरोल ब्लाक के ग्राम मऊ में दोपहर 12 बजे से कृषि ऋण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला अग्रणी प्रबंधक राहुल रैकवार ने बताया की शिविर में किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि यंत्र ऋण, डेयरी एवं पशुपालन ऋण, बागवानी ऋण आदि योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र किसानों के ऋण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे तथा ऋण वितरण किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य बैंक द्वारा चलाई जा रही ऋण योजनाओं की जानकारी देना है जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके तथा वे आत्मनिर्भर बन सके।

उड़ान स्कूल का नवनियुक्त सी ईओ साकिब आलम ने किया निरीक्षण

नसीराबाद (हुक्मनामा समाचार)।अजमेर हनुमान चौक पर स्थित विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संचालित उड़ान स्कूल का नवनियुक्त छावनी परिषद सीईओ साकिब आलम व कर्नल मनिंदर सिंह ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया बच्चों से व उनके परिजनों से भी रूबरू हुए व छावनी परिषद के आकाश जेदिया से स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर दिशानिर्देश दिए व इस मौके पर छावनी परिषद अधिदर्शक विश्वेंद्र सिंह फिजियोथैरेपिस्ट डॉक्टर लक्षिका स्पीच थैरेपिस्ट भारती नागवान विशेषशिक्षिका कृष्ण शर्मा व कार्मिक मंजू देवी पवित्रा मौजूद रहे नवनियुक्त सी ईओ साकिब आलम ने बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले उन्होंने उड़ान स्कूल का निरीक्षण किया सीईओ साकिब आलम ने मौजूदपरिजनों को आश्वस्त किया कि स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी

घूमर शो एवं लोकल टेलेंट हंट के लिए 18 फरवरी तक भेज सकते हैं नाम

कोटा महोत्सव के तहत आयोजित होगा फोटो कॉन्टेस्ट, 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक प्रविष्टियां आमंत्रित

कोटा (हुक्मनामा समाचार)। 21 एवं 22 फरवरी को कोटा महोत्सव के तहत आयोजित होने वाली फोटो कॉन्टेस्ट एवं एग्जीबिशन के लिए 15 फरवरी तक प्रतिभागियों से एंट्री ली जाएंगी। फोटो कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले प्रतिभागी कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों, दर्शनीय स्थलों एवं वन्य जीवन से संबंधित स्वयं द्वारा खींची गई फोटो कॉन्टेस्ट के लिए 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक भेज सकेंगे। फोटो कॉन्टेस्ट के लिए प्रोफेशनल कैमरा एवं मोबाईल से खींची गई फोटो की अलग-अलग एंट्री ली जाएंगी। इसके लिए उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा अनुराग भट्ट नागर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रतिभागी अपनी चयनित फोटो की एंट्री के लिए उप वन संरक्षक वन्य जीव कार्यालय स्टेडियम के सामने नयापुरा कोटा में भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कोटा महोत्सव के तहत 21 फरवरी को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकल टेलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसके लिए 11 से 18 फरवरी तक प्रतिभागी अपना नाम भेज सकते हैं। लोकल टेलेंट हंट के तहत एकल एवं सामूहिक नृत्य तथा गायन के लिए अपना नाम भेजा जा सकता है। कोटा महोत्सव में 21 फरवरी को सायं 4 से 5 बजे तक आयोजित होने वाले घूमर शो के लिए भी प्रतिभागियों से नाम आमंत्रित किए गए हैं। घूमर शो के लिए प्रतिभागी 11 से 18 फरवरी तक अपने नाम भेज सकते हैं। लोकल टेलेंट हंट प्रतियोगिता एवं घूमर शो में शामिल होने के लिए प्रतिभागी 18 फरवरी तक सायं 6 से 9 बजे तक प्रधानाचार्य संगीत महाविद्यालय रामपुरा कोटा राजकुमार कनाडा से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कोटा महोत्सव के तहत 21 फरवरी को आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्यूआर कोड भी दिया गया है। इस क्यूआर कोड को मोबाईल से स्कैन कर अपना नाम भेजा जा सकता है। प्रतिभागी कोटा महोत्सव के तहत आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निम्न लिंक https//forms.gle/DdQXKnuqaQmpXmzw| के माध्यम से भी करवा सकते हैं।

बजट पर प्रतिक्रिया

अजमेर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में एंव उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री दियाकुमारी जी द्वारा पेश किया गया बजट विकसित और आत्मनिर्भर एंव दुरदर्शिता पूर्ण हैं, आने वाले समय में राजस्थान का सर्वागीण विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला हैं। बजट में शिक्षा चिकित्सा, सडक, परिवहन, रोजगार कृषि और किसान के लिये विशेष योजनाओ की घोषणा हुई हैं, भीलवाडा शहर और जिले को मिली सोगाते आने वाले समय में भीलवाडा को विकास की राह पर ले जायेगी।

जैन ट्रस्ट की करोड़ों की जमीन पर फर्जी बेचान का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपी फरार

भीलवाड़ा,(हुक्मनामा समाचार)। शहर के सांगानेरी गेट स्थित उपासरा यति श्री केसरीचंद संपत्ति ट्रस्ट, शांतिनाथ जैन मंदिर की करोड़ों रुपये की जमीन के कथित फर्जी बेचान का मामला तूल पकड़ गया है। जैन समाज के पदाधिकारियों और सैकड़ों लोगों द्वारा जिला व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद सुभाष नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338 व 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच थानाधिकारी कैलाश चंद्र विश्नोई कर रहे हैं। 70-80 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति के नाम से दस्तावेज तैयार करने का आरोप प्रकरण के अनुसार ट्रस्ट की सुवाणा कस्बे में स्थित करीब दो बीघा चार बीसवा कृषि भूमि (खसरा नंबर 1985) का 17 अक्टूबर 2025 को 19 लाख 50 हजार रुपये में बेचान कर दिया गया। आरोप है कि यह सौदा 70-80 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता खुलवाकर किया गया। रजिस्ट्री में खरीदार के रूप में आसींद निवासी मुन्ना मोहम्मद पुत्र अब्दुल मजीद शेख का नाम दर्ज है। दस्तावेजों के अनुसार भुगतान एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते से चेक संख्या 000049 के माध्यम से किया गया। रजिस्ट्री में एक लाख रुपये के स्टाम्प लगाए गए तथा उपपंजीयक कार्यालय द्वारा खातेदारी अधिकार भी स्थानांतरित कर दिए गए। गवाहों के रूप में रामकरण जाट (ग्राम खजीना, आकोला) और मुबारिक हुसैन (गुलअलीनगरी, भीलवाड़ा) के नाम दर्ज हैं। पड़ोसी से मिली जानकारी, तब खुला मामला समाज के सुवाणा निवासी एवं श्रीसंघ के उपाध्यक्ष प्रकाश चपलोत जैन को भूमि के पड़ोसी गोपाल साधु दादूपंथी से बेचान की जानकारी मिली। इसके बाद समाज में रोष व्याप्त हो गया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। शहर में बिखरी पड़ी हैं ट्रस्ट की संपत्तियां बताया जा रहा है कि ट्रस्ट की शहर के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियां हैं। समाज की अनदेखी के चलते कई स्थानों पर कथित रूप से अवैध कब्जे और कच्चे-पक्के निर्माण हो चुके हैं। कुछ मामलों में नगर विकास न्यास में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर पट्टे बनवाने के आरोप भी सामने आए हैं। सांगानेरी गेट स्थित मंदिर के सामने छतरियों वाली जमीन का मामला भी चर्चा में है।

ऑपरेशन चंगुलः जिला कलक्टर ने एम.जी. रोड स्थित दुकानों के प्रकरण का किया मौके पर निरीक्षण

प्रतापगढ़। एम.जी. रोड पर दरगाह काका साहब के सामने स्थित दुकानों के संबंध में प्राप्त शिकायत पर जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऑपरेशन चंगुल के तहत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित पक्षों से जानकारी प्राप्त की गई तथा विवादित दुकानों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी पक्ष के पास मालिकाना अधिकार अथवा वैध किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हों तो उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

बजट शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रीय विकास इंफ्रा सौंदर्य करण और रोजगार सृजन को देगा बढ़ावा-: रिजु झुनझुनवाला

भीलवाड़ा,(हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान सरकार की बजट पर आरएसडब्ल्यूएम भीलवाड़ा ग्रुप की ओर से श्री रिजु झुनझुनवाला ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल के सफल मार्गदर्शन और वित्त मंत्री सुश्री दिया कमारी जी का आभार व्यक्त किया। यह बजट विकास ,विनिर्माण को बढ़ावा, एमएसएमई को समर्थन, निर्यात प्रोत्साहन और व्यापार करने में आसानी को मजबूत करने वाला है। श्री झुनझुनवाला ने कहा कि भीलवाड़ा, जो देश का प्रमुख कपड़ा हब इस बजट से सीधे लाभान्वित होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आधुनिक मशीनरी, बुनियादी ढांचे का विस्तार,

लॉजिस्टिक्स सहायता और कौशल विकास, रोजगार सृजन से यहां की वस्त्र उपक्रम इकाइयां और मजबूत होंगी। इससे अलावा उत्पादन क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। भीलवाड़ा में नए निवेश, मूल्यवर्धन, हरित ऊर्जा का उपयोग और निर्यात वृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

राजसखी कोटा मेला-2026 आज

कोटा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा राजसखी कोटा मेला-2026 का आयोजन 12 से 18 फरवरी तक किया जाएगा। मेले में राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र पंजाब, मध्य प्रदेश आदि कई स्थानों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की भव्य प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। मेले में देश के कई राज्यों और प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रसिद्ध उत्पादों के साथ-साथ अलग-अलग जगह के प्रसिद्ध व्यंजन भी फूड कोर्ट में देखने को मिलेंगे।

खोया पाया सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे द्वारा जो कि नगर परिषद ब्यावर तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राजस्थान की सीमा में स्थित बजाज नगर, ब्यावर की निजी सम्पत्ति में आबादी में स्थित भूखण्ड नं 18 जिसका कुल क्षेत्रफल 120 वर्गगज है मय इस पर निर्मित एक मंजिला पट्टी पोश जायदाद के बख्शीश नामा दिनांक 27.03.2025 के पूर्व के तमाम चैनल कागजात हमारे द्वारा कही पर गिर गये है जो काफी ढूंढने से भी नही मिले है तथा जिस किसी को मिले कृपया सुचित करे। **श्रीमति निशा गर्ग व श्रीमति विमला देवी, अग्रवाल निवासी ब्यावर, राजस्थान। मो. नं.-92143 52763**

साईकिल पाकर बालिकाओं के चेहरे खिले बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया

ब्यावर,(हुक्मनामा समाचार)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपनगर अरनाली बड़ाखेड़ा में बालिकाओं का साईकिल का वितरण किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक सुरेश चन्द फुलवारी ने बताया कि विद्यालय के संस्था प्रधान जमालुद्दीन ने बालिकाओं को साईकिल भेंट की। इस अवसर कक्षा नौ की बालिकाओं को साईकिल दी गई । साईकिल प्राप्त कर बालिकाओं की खुशी का ठीकाना नहीं रहा। संस्था प्रधान ने छात्राओं को नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगा कर अध्ययन करने और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के ओमप्रकाश,सुभाष चन्द यादव, अजय कुमार ,फोरंती मीणा,हरि प्रसाद सेपट, पृथ्वीराज सिंह चौहान,शिव प्रकाश मीणा और रवि कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे।

बीएल गोठी स्कुल की सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हुआ

साथ बिताए गए सुखद पलों को संजोने का एक उत्सव

ब्यावर ,(हुक्मनामा समाचार)। वर्द्धमान शिक्षण समिति ब्यावर द्वारा संचालित भंवरलाल गोठी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा सीनियर सेकेंडरी (बारहवीं) के विद्यार्थियों के विदाई समारोह में भारतीय संस्कार, संस्कृति एवं स्मृतियों का अनूठा संगम देखने को मिला।

समस्त सीनियर स्टूडेंट के सिर पर साफे, ललाट पर कुमकुम का तिलक, गाजे बाजे के साथ द्वार पर विद्यालय के शिक्षक गणों एवं जूनियर स्टूडेंट द्वारा भावभीना अभिनंदन किया गया। उत्साह और उमंग से भरे इस विदाई समारोह का आयोजन कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों और शिक्षकों द्वारा वर्द्धमान ऑडिटोरियम में किया गया। यह दिन दोस्तों और शिक्षकों के साथ बिताए गए वर्षों को याद करने

और सुखद पलों को संजोने का एक उत्सव था। कार्यक्रम का शुभारम्भ कक्षा बारहवीं के समस्त विद्यार्थियों को साफा पहनाकर व रोली चावल से तिलक कर स्वागत किया गया तथा समस्त अभिभावकों को पुष्प गुच्छ भेट कर विद्यालय बैंन्ड द्वारा विद्यालय परिसर से महाविद्यालय सभागार तक मुधर ध्वनि के साथ लाया गया। समस्त विद्यार्थी बैंड की सुमधुर धुनों पर आनंदित भाव से झूमते नजर आए। सभागार में समारोह का शुभारंभ श्री वर्द्धमान शिक्षण समिति के मंत्री डॉ नरेंद्र पारख, निदेशक एवं कॉलेज प्राचार्य डॉ आर.सी.लोढ़ा, गोठी स्कूल प्राचार्य धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, उप प्राचार्या सुनिता चौधरी ने संबोधित करते हुए छात्राओ को शुभकामनाए प्रष्ज्ञित की। अतिथियों का स्वागत सत्कार बुके देकर किया गया। इसके पश्चात मंच पर समस्त आगंतुक अभिभावकों, अतिथियों के समक्ष सीनियर विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले स्मृति छाया चित्र का विमोचन किया गया।

कृषि ऋण शिविर का आयोजन कल

कोटा। किसानों को सुलभ एवं त्वरित ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 13 फरवरी को जिले के ग्राम बडौद स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडौद में दोपहर 2 बजे से कृषि ऋण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में किसानों को फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि यंत्र ऋण, डेयरी एवं पशुपालन ऋण, बागवानी ऋण आदि योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही, पात्र किसानों के ऋण आवेदन स्वीकार कर मौके पर ही ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया भी की जाएगी।

जन्म मृत्यु सूचना

में विकास पुत्र सोहन लाल निवासी प्लॉट नं. 10 सुरेश नगर बलाड़ रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राजस्थान शपथ पूर्वक बयान करता हु कि मेरी पुत्री आकांक्षा का जन्म 15-05-2022 को उपरोक्त पते मेरे घर पर हुआ है। मैने पूर्व में कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। अतः मैने मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

विकास पुत्र सोहन लाल निवासी प्लॉट नं. 10 सुरेश नगर बलाड़ रोड ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला ब्यावर राजस्थान।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन /2025-26/2053 दिनांक :- 11.02.26

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात

क्र. सं.	आवेदन का नाम	ग्राम	खसरा न0	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	आशीष अग्रवाल पुत्र निरंजन अग्रवाल हिस्सा पूर्ण जाति अग्रवाल मकान संख्या 28 कॉलोनी बालाजी नगर विहार क्षेत्र/स्थान-वैशाली नगर शहर-अजमेर, पिन कोड 305001 जिला अजमेर राज्य-राजस्थान खातेदार।	सेदरिया	62 63	0.1174 हैक्टेयर 0.1174 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 11.02.2026 जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी
नगर परिषद ब्यावर

भाजपा ने बजट को सराहा, कांग्रेस ने बताया निराशाजनक

ब्यावर,(हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में वित मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश बजट पर भाजपा अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि यह बजट राजस्थान की 8 करोड़ जनता की उम्मीदों को पूर्ण करने वाला बजट है जो आत्मनिर्भर और 'समृद्ध राजस्थान' की ओर बढ़ते कदम में तीव्रता लाने के साथ ही हर राजस्थानी के सपनों को साकार करने का रोडमैप है। प्रदेश की डबल इंजन सरकार अंत्योदय और सुशासन को समर्पित है। किसान, युवा और महिला की उन्नति को समर्पित यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। वही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अशोक रांका ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक बजट है। इसमें युवाओं और किसानों को, मजदूरों को,केवल एक लॉलीपॉप दी गई है इससे कुछ होने वाला नहीं है इसके लिए सरकार को धरातल पर उतरना पड़ेगा एवं ब्यावर जिले वासियों को बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन आमजन को इससे निराशा हाथ लगी है जिला बनने के बाद भी ब्यावर वासियों को कुछ भी नहीं मिला।

रावतभाटा परमाणु बिजली घर में आपदा की हुई मॉक ड्रिल

कोटा,(हुक्मनामा समाचार)। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातकाल की तैयारियां परखने के लिए चित्तौडगड जिले के रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर के आसपास के विभिन्न गांवों में बुधवार को आपदा प्रबंधन से संबंधित ऑफ साइट इमरजेंसी के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमाण्ड रेस्पॉन्स एक्सरसाइज (आईसीसीआर) की गई। इस ऑफ साइट मॉक ड्रिल के माध्यम से जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन से जुडी विभिन्न एजेंसियों एवं विभागों की तैयारियों की जांच की गई।

ब्यावर जिले के जैतारण को बालिका हॉस्टल की सौगात

ब्यावर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को लगातार तीसरा आम बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। बजट में ब्यावर जिले के जैतारण क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है। इसके तहत जैतारण में सावित्री बाई फुले छात्रावास के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। जैतारण के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने इस घोषणा को क्षेत्र की बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आवास की समस्या से निजात दिलाएगा। मंत्री गहलोत ने आगे कहा कि इससे बालिकाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत किया है।

कलक्टर ने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम व भू-अभिलेख अनुभाग का किया औचक निरीक्षण

साफ-सफाई एवं रिकॉर्ड व्यवस्था पर जताई नाराजगी

चित्तौड़गढ़,(हुक्मनामा समाचार)। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने बुधवार को दोपहर बाद कलक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम एवं भू-अभिलेख अनुभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। जिला कलक्टर ने वहा पर लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित ढंग से संधारित किया जाए तथा रिकॉर्ड रूम में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका सुरक्षित एवं व्यवस्थित रख-रखाव अनिवार्य है। उन्होंने रिकॉर्ड रूम में अनावश्यक व नाकारा सामग्री के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए, ताकि आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और कार्य में सुगमता बनी रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूमि अवाप्ति) रामचंद्र खटीक भी उपस्थित रहे।

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन /2025-26/2057 दिनांक :- 11.02.26

लोक सूचना

निम्नांकित खातेदारों ने इस कार्यालय में निचे उल्लेखित भूमि का गैर कृर्षिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात

क्र. सं.	आवेदन का नाम	ग्राम	खसरा न0	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	1. आलम काठात पुत्र रोशन काठात हिस्सा 1/2 जाति मेरात निवासी जालिया प्रथम तहसील ब्यावर जिला ब्यावर खातेदार। 2.शौकीन खान पुत्र ईस्माइल खान हिस्सा 1/4 जाति मेरात निवासी लसाडिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर खातेदार। 3.हीरा काठात पुत्र बाबू काठात हिस्सा 1/4 जाति मेरात निवासी नीमगढ तहसील मसूदा जिला ब्यावर खातेदार।	गढीथोरियान	1649 2219/1658	0.1700 हैक्टैयर 0.7082 हैक्टैयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधिन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष के समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 11.02.2026 जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी
नगर परिषद ब्यावर

नागौर बोर्ड परीक्षाओं को मध्यनजर रखते हुए डीजे बजाने पर पुलिस ने एक और डीजे को किया जब्त

नागौर,(हुक्मनामा समाचार)। पुलिस द्वारा शिक्षण संस्थाओं के पास डीजे बजाने पर प्रभावी कार्यवाही। एक डीजे जब्त किया गया। अलर्ट मोड पर है एसपी मुदुल कच्छावा के निर्देशानुसार नागौर शहर व जिले में रात 10 से सुबह 6:00 तक डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, नागौर में बोर्ड परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर के पास डीजे बजाने पर डीजे को जब्त कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला परिवहन विभाग को सूचना दी गई। बोर्ड परीक्षाओं के मध्यनजर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। थाना कोतवाली नागौर पुलिस टीम की रही कार्यवाही नागौर एसपी मृदुल कच्छावा आई पी एस पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के द्वारा आगामी बोर्ड अन्य परीक्षाओं के मध्यनजर ध्वनि प्रदूषण डीजे म्यूजिक सिस्टम की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों की पालना में आशाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर तथा धर्मचंद पूनिया वृताधिकारी वृत्त नागौर के निकटतम सुपरविजन में वेदपाल शिवराण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, शहर में स्कूल परिसरों के आस-पास डीजे बजाते हुए एक डीजे जब्त किया गया।

उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए 9 मार्च से करें आवेदन

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा, 2023 के अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का अवसर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया और समय-सीमा आयोग सचिव ने बताया कि , जो अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करना चाहते हैं, वे 9 मार्च से 8 अप्रेल 2026 तक आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इनफॉर्मेशन सेक्शन में जाकर आरएस (मैन) एग्जाम 2023 के लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर, आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर लॉगिन करना होगा। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए प्रति पुस्तिका 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान शुरू

यदि शुल्क वापस नहीं लिया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी : रांका

ब्यावर ,(हुक्मनामा समाचार)। ब्यावर में नगर परिषद द्वारा लगाए गए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुल्क के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह अभियान वार्ड नंबर 18 स्थित गजानंद जी मंदिर, चमन चौराहा से औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ। निवर्तमान पार्षद भरत बाघमार के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने शुल्क के विरोध में हस्ताक्षर एकत्र किए। इस दौरान आम जनता ने भी नगर परिषद के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस के अभियान का समर्थन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक रांका ने इस अवसर पर कहा कि नगर परिषद द्वारा लगाया गया कचरा संग्रहण शुल्क आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। उन्होंने इसे वर्तमान महंगाई के दौर में अनुचित बताया। रांका ने चेतावनी दी कि यदि शुल्क वापस नहीं लिया गया, तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र तुनगरिया ने बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को जोडना है। उन्होंने कहा कि एकत्रित हस्ताक्षरों को जल्द ही जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी जनहित के मुद्दों पर हमेशा आमजन के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जनविरोधी नीति का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रहेगा।

माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड

(पूर्वआदर्शको-ऑपरेटिवबैंकलिमिटेड)
शाखा किशनगढ़ (01463) 245668 मो. 9983094564, 9414152572

अधिग्रहण (कब्जा) सूचना

[परिष्टि 4 नियम 8(1) कब्जे की सूचना (स्थावर सम्पति के लिये)]

यहवित्तीय आस्तियोंका प्रतिभूतिकरणऔर पुनर्गठनऔर प्रतिभूतिहित प्रवर्तनअधिनियम 2002, (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अन्तर्गत और धारा 13(12) के संपादित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के अधिन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए,माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 11.06.2025 को जारी किया, जिसमें ऋण खाता संख्या एमबी-23 में ऋणी मैसर्स. श्री तेजा पॉलीपैक प्रो0 दीपा शर्मा (ऋणी) 2.श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री बंशी लाल (जमानती एवं रहनकर्ता स्व. श्री बंशी लाल पुत्र भंवर लाल के विधिक उत्तराधिकारी) 3. श्री प्रदीप पुत्र श्री बंशी लाल (जमानती एवं रहनकर्ता स्व. श्री बंशी लाल पुत्र भंवर लाल के विधिक उत्तराधिकारी) 4. श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री बंशी लाल (जमानती एवं रहनकर्ता स्व. श्री बंशी लाल पुत्र भंवर लाल के विधिक उत्तराधिकारी) 5. श्रीमती हेमलता पुत्री श्री बंशी लाल भी (जमानती एवं रहनकर्ता स्व. श्री बंशी लाल पुत्र भंवर लाल के विधिक उत्तराधिकारी) 6. श्री संजय पुत्र श्री बंशी लाल (जमानती एवं रहनकर्ता स्व. श्री बंशी लाल पुत्र भंवर लाल के विधिक उत्तराधिकारी) 7. श्री जाकिर हुसैन पुत्र कालूखान (जमानती)को नोटिसमें ऋणखाता संख्याएमबी-23 मेंउल्लेखित राशिरू. 2,59,158.09 (रूपये दो लाख उनसठ हजार एक सौ अठावन एवं नो पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2025 तक ब्याज सहित तथा ब्याज, पैनल ब्याज व अन्य खर्च इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिये कहा गया था। ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतदद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 03.02.2026 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पति को कब्जे में लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतदद्वारा सम्पति के साथ कोई संव्यवहार नही करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार ऋण खाता संख्या एमबी-23 में उल्लेखित राशि रू. 2,56,485.09 (रूपये दो लाख छप्पन हजार चार सौ पिचायसी एवं नो पैसे मात्र) दिनांक 31.01.2026 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इससे आगे का ब्याज, पैनल ब्याज व अन्य खर्चे माउण्ट नागरिक सहकारी बैंक लि. शाखा किशनगढ़ (राजस्थान) के प्रभार के अधिन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों को छुडाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचलसम्पतिकावर्णनः

सम्पति के सभी अंश व अंग गठित होते है जो अचल सम्पति जो गांव बुबानी जिला अजमेर स्थित है। जिसका पट्टा नं. 9, बुक नं. 58 दिनांक 05.05.2012 है। सम्पति का कुल क्षेत्रफल 1271 वर्गफीट है। सम्पति का पट्टा ग्राम पंचायत बुबानी पंचायत समिति श्रीनगर जिला अजमेर में द्वारा दिनांक 31.03.2013 को बुक नं. 1, वोल्यूम नं. 1791, क्र.सं. 2013001929, अतिरिक्त बुक नं. 1, वोल्युम नं. 4158 पेज नं. 211 से 214 से पंजीकृत है। यह सम्पति श्री बंशीलाल पुत्र श्री भवंरलाल द्वारा रहन रखी गयी है। जिसकी चारो ओर की सीमाएं निम्न है :-

उत्तर : लालनाथ का मकान, दक्षिण : आम रास्ता, पूर्व : श्री जीवन नाथ का मकान एवं पश्चिम : प्राईवेट मकान एवं तेजाजी मंदिर

स्थानःसिरोही,राजस्थान
दिनांकः03.02.2026

प्राधिकृतअधिकारी
माउण्टनागरिकसहकारीबैंकलि.

अच्छे संस्कार ही नैतिकता के मार्ग का आधार हैं : डॉ. अतुल कोठारी

बांदरसिंदरी (हुक्मनामा समाचार)। कस्बे में स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय कार्यशाला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की गई । कार्यशाला के उद्घाटन पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रसिद्ध शिक्षाविद् और राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, के डॉ. अतुल कोठारी ने कहा कि 'अच्छी आदतें ही वास्तविक मूल्यों की पहचान होती हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण करता है, वही नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर रहता है। डॉ. कोठारी ने अपने अभिभाषण में पंचकोश सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश की व्याख्या की तथा प्रत्येक कोश को दैनिक जीवन के सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया। उन्होंने प्रतिभागियों को इन कोशों

के भावार्थ को आत्मसात करने एवं नियमित अभ्यास द्वारा इन्हें जीवन में उतारने का सुझाव दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश को अपरिहार्य बताया। उन्होंने वर्तमान समय को 'चरित्र संकट' का दौर बताते हुए कहा कि समाज की अनेक समस्याओं की जड़ नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट है, तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनुष्य को 'व्यक्ति' इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने विचारों, भावनाओं एवं कर्तव्यों को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। डॉ कोठारी ने यह आह्वान किया कि हम सब सीखने की प्रक्रिया में आजीवन विद्यार्थी बने रहें, क्योंकि निरंतर सीखना ही व्यक्तित्व विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि खेलकूद, स्वच्छता एवं अनुशासित जीवनशैली से शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं मन को शांत रखना मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान एवं विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से होता है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक व अध्यक्ष, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास केवल एक संस्था नहीं हैं, यह भारत की शिक्षा-आत्मा को पुनर्जीवित करने का आंदोलन हैं। न्यास हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि मनुष्य का निर्माण हैं। इससे पूर्व दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ जिसके पश्चात कुलपति प्रो आनंद भालेराव ने मुख्य अतिथि डॉ. अतुल कोठारी का शॉल, स्मृति चिन्ह व भगवद गीता भेंट कर स्वागत किया। इसी क्रम में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रीय सह संयोजक डॉ. हार्दिक पाठक ने कुलपति प्रो आनंद भालेराव का भगवद गीता भेंट कर स्वागत किया।

साँची मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 'सरस्वती वंदना' ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया ।कार्यक्रम के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह ने मुख्य अतिथि डॉ. अतुल कोठारी का परिचय प्रस्तुत किया

न्यूज ब्रीफ

भीलवाड़ा के सर्वांगीण विकास को समर्पित ऐतिहासिक बजट हर वर्ग के लिए खुली खुशहाली की राह

भीलवाड़ा (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री दियाकुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे संपूर्ण प्रदेश के साथ ही भीलवाड़ा के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ीकरण का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भीलवाड़ा जिले की आम जनता की जरूरतों को समझते हुए युवा, महिला, किसान, उद्यमी, गरीब और कर्मचारी वर्ग के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, जल, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे जिले के भविष्य को स्वर्णिम बनाएंगी ।जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि जिलाध्यक्ष मेवाड़ा ने भीलवाड़ा जिले की सभी विधानसभाओं भीलवाड़ा, मांडल, सहाड़ा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ को इस बजट में अनेक सौगाते दिए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं इन क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मेवाड़ा ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के संकल्प को सिद्ध करने वाला है, जो भीलवाड़ा को आधुनिकता और आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

एलिवेटेड रोड व लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा ऐतिहासिक : सांसद अग्रवाल

भीलवाड़ा (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान बजट 2026 को लेकर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे विकासोन्मुखऔर सर्वसमावेशी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा के लिए एलिवेटेड रोड और लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा जिले के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों और यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी ।सांसद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट पेयजल, अन्नदाता किसानों, गरीबों, युवाओं,

महिलाओं और उद्योग जगत को समर्पित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार के लिए 1400 करोड़ रुपये तथा मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरओबी और आरयूबी निर्माण के लिए 920 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। बालिकाओं की शिक्षा, आत्मरक्षा और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के लिए प्रदेश के 300 से अधिक महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेशभर में 7 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी व सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। सांसद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट 'संकल्प से सिद्धि' की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने भीलवाड़ा जिले के लिए की गई घोषणाओं पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई ऊंचाई

पाटन-किशनगढ़ सड़क के लिए 35 करोड़ की स्वीकृति

मदनगंज किशनगढ़ (हुक्मनामा समाचार)। अजमेर संसदीय क्षेत्र के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान बजट 2026-27 के अंतर्गत पाटन से किशनगढ़ वाया तिलोनिया-हरमाड़ा- भोजियावास सड़क के निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान किए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है। चौधरी ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा। इससे स्थानीय किसानों, व्यापारियों एवं आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई यह घोषणा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

स्वस्थ माँ-स्वस्थ शिशु संबंधी रोचक और आसान भाषा में मिल रही जानकारी

बूँदी (हुक्मनामा समाचार)। चिकित्सा विभाग की ओर से स्वस्थ मां एवं सशक्त शिशु के संबंध में जागरूकता बढाने के लिए एक अनुपम पहल की गई है। इसके लिए यूट्यूब चैनल गर्भ की पाठशाला शुरू किया गया है। इसमें प्रदेशवासियों को स्वस्थ मां और सशक्त शिशु से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जा रही है ।मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में निरामय राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह अभिनव पहल की गई है ।स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय स्तर से संचालित इस यूट्यूब चैनल से अब घर बैठे महिलाएं व आमजन लाभान्वित हो रहे हैं।

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम तथा निदेशक आईईसी डॉ टी शुभमंगला द्वारा शुरू करवाए गए इस गर्भ की पाठशाला चैनल पर सभी जानकारी बेहद रौचक व आसानी भाषा में आमजन को उपलब्ध

करवाई जा रही है। वहीं आम महिला की समझ में आ सके(इसलिए साधारण हिंदी भाषा में फिल्म, डाईग्राम के माध्यम से समझाई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओ पी सामर ने इस पाठशाला को आमजन के लिए बेहद लाभादायक बताते हुए कहा कि इसमें मेडिकल टर्मनॉलोजी को आसान हिन्दी भाषा बताया गया है, ताकि लोगों को गर्भवस्था में रखी जाने वाली सावधानियां, जौखिम, एनीमिया प्रबंधन, शिशु की देखभाल जैसी उपयोगी जानकारी मिल सके। राजस्थान आईईसी ब्यूरों द्वारा संचालित गर्भ की पाठशाला चैनल पर फिल्म, डायग्राम के माध्यम से गर्भावस्था की पहचान, गर्भावस्था में एनीमिया, गर्भधारण पूर्व परामर्श, गर्भावस्था के दौरान उल्टी, गर्भावस्था में जरूरी पोषण, सुरक्षित गर्भपात, पूर्व

बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बूंदी (हुक्मनामा समाचार)। परीक्षाओं के सीजन को देखते हुए और विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर/डीजे) के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी हैं। यह प्रतिबंध 18 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा ।जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा, अप्रैल में जेईई-मेन (सत्र-2), 3 मई 2026 को नीट और 17 मई 2026 को जेईई-एडवांस्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोलाहल से परेशानी न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। आदेशानुसार राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा-5 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार, अब किसी भी प्रकार के आयोजन में लाउडस्पीकर या डीजे बजाने के लिए स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों की अवहेलना करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, संबंधित उपकरण और वाहन को जब्त करने की कार्यवाही होगी। साथ ही, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

नाथुथला में नरेगा श्रमिकों को दी बीवी जी राम जी योजना की जानकारी, 115 में से 104 श्रमिक मिले उपस्थित

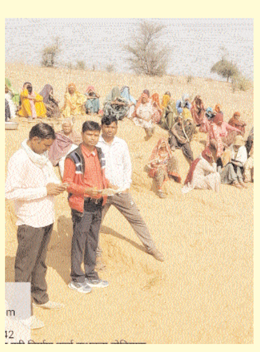

मांगलियावास (हुक्मनामा समाचार)। डोडीयाना ग्राम पंचायत के नाथुथला गांव में बुधवार को कनिष्ठ सहायक गणपत खारोल ने विकास अधिकारी सोहनलाल डारा के निर्देशन में पंचायत क्षेत्र में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान नरेगा कार्यों का अवलोकन करते हुए कालू के खेत के पास चल रहे सार्वजनिक नाडी निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे, जहां कुल 115 में से 104 श्रमिक उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान मेट मेवा चीता, रमेश चंद कुमावत और जमील चीता को कार्य की प्रगति व व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही कार्यस्थल पर मौजूद श्रमिकों को महानरेगा के नए संस्करण बीवी जी राम जी योजना की विस्तार से जानकारी देकर इसके लाभ और प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया।

मांगलियावास में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र कुमावत ने ग्रामीणों को दी बजट की जानकारी

मांगलियावास (हुक्मनामा समाचार)। ग्राम मांगलियावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र कुमावत ने राजस्थान के बजट की जानकारी आमजन तक पहुंचाई। उन्होंने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बजट की प्रमुख योजनाओं और प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया तथा सभी को शुभकामनाएं भी दीं। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विकास और संगठन की मजबूती पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, युवा नेता एडवोकेट हंसराज चौधरी, पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट प्रदीप कुमार, किसान मोर्चा अध्यक्ष शिवजीराम जाखड़, एससी मोर्चा अध्यक्ष शिवराज मेघवाल, मीडिया मंत्री देवी सिंह रावत, बलवीर सिंह गौड़, राकेश संचेती, मनीष पुनिया, राजु सारस्वत, जयदीप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार का बजट श्खोखले वादों का पुलिंदाश् और श्जनता के साथ छलावा : आंजना

निम्बाहेड़ा (हुक्मनामा समाचार)। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा आज विधानसभा में पेश किया गया वार्षिक बजट पूरी तरह से दिशाहीन और निराशाजनक है। यह बजट धरातल की सच्चाई से दूर, केवल आंकड़ों की बाजीगरी और चुनावी घोषणाओं का एक पिटारा मात्र है, जिसमें आम आदमी के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। आंजना ने कहां की बढ़ता कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकार राज्य को कर्ज के दलदल में धकेल रही है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। बिना आय के स्रोतों पर ध्यान दिए की गई घोषणाएं केवल आर्थिक अस्थिरता को बढ़ाएंगी।

नैनवा में निर्माणाधीन उप जिला चिकत्सालय बिल्डिंग का औचक निरीक्षण

बूँदी (हुक्मनामा समाचार)। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ. पी. सामर ने खंड नैनवा स्थित निर्माणाधीन उप जिला चिकत्सालय की बिल्डिंग का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का गहन परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति, ट्रोमा सेंटर सहित निर्धारित मानकों के पालन तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता से समझौता किए बिना पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। निरीक्षण के उपरांत डॉ. सामर ने उप जिला अस्पताल का निरिक्षण किया इस दौरान उन्होंने, पर्ची काउंटर, दवाइयां साफ सफाई, लेबर रूम, बायोमेडिकल वेस्ट, शौचालय सहित नि:शुल्क जाँच एवं अन्य का गहन निरिक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए निरिक्षण के बाद उन्होंने खंड नेनवा की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय कार्यक्रमों की बिंदुवार प्रगति जानी। बैठक में आभा आईडी निर्माण, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम, मां वाउचर योजना तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय टीम के निरिक्षण को देखते पूर्ण तैयारी रखने, डीजिटल हेल्थ के चलते ऑनलाइन पर्ची शुरू कर कराउड कंट्रोल के सख्त निर्देश दिए उन्होंने सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, रोगों की समय पर पहचान, स्क्रीनिंग गतिविधियों में तेजी तथा रेफरल व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य टीमों को आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने को कहा।

विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि आदान विक्रेताओं का सघन निरीक्षण

निम्बाहेडा (हुक्मनामा समाचार)। अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड भीलवाड़ा श्री इन्द्र सिंह संचेती एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद चित्तौड़गढ़ डॉ. शंकर लाल जाट के निर्देशन में जिले में विशेष गुण नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कृषि आदान विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूने लिए गए ।इस क्रम में लक्ष्मी धाकड़ बीज भंडार शंभूपुरा, श्रीश्याम बीज भंडार शंभूपुरा, भंडारी मशीनरी मार्ट चित्तौड़गढ़, गणपति फर्टिलाइजर्स गोराजी का निम्बाहेड़ा, बालाजी बीज भंडार कनेरा, राम कृषि सेवा केन्द्र कनेरा, कोठारी ट्रेडर्स बस्सी सहित विभिन्न विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया गया।

वित्तीय समावेशन तथा लिंकेज कैंप का आयोजन बेमौठ में किया गया

मौलासर (हुक्मनामा समाचार)। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत क्रिसिल फाउंडेशन मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र डीडवाना केंद्र प्रबंधक सुमित्रा सिहाग सहित ग्रामीण लोगों ने भाग लिया वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरे जिले भर में चल रहा है जिसमें बैंक की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगो को जागरूक किया जा रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना बचत चालू खाता फिक्स डिपोजिट आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई साथ वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए भी जागरूक किया ओर किसी अनजान लोगों के साथ अपने जरूरी डॉक्यूमेंट ओटीपी नहीं बताए और अनजान लोगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करे और अपने खाते को किसी ओर के साथ शेयर ना करे और किसी पोजी योजनाओं ओर लॉटरी लुभाने वाली स्कीमों में निवस ना करे और भविष्य के लिए बचत करने की आदत डाले और किसी भी तरह की फ्रॉड होने पर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाए इस दौरान ग्रामीणों के क्क्क बैंक क्ष्ट रामवतार प्रजापत ने योजनाओं से लिंकेज किए गए

राजस्थान बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया............

बजट में युवाओं को पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं की सौगात, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना का फैसला स्वागत योग्य

बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान : मदन राठौड़

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजस्थान बजट 2026—27 को विकसित राजस्थान के निर्माण का सशक्त और दूरदर्शी रोडमैप बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर करने वाला है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट आमजन, किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी और उद्योग जगत सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। बजट में आधारभूत ढांचे के विस्तार, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि बजट में 42 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। जोधपुर, पाली, मारवाड औद्योगिक कॉरिडोर 600 करोड की सहायता से, सीएम स्वरोजगार योजना से 10 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त सहायता, ग्रामीण महिला बीपीओ खोलना, पारदर्शी परीक्षा के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण सीमा 50 लाख से बढाकर 1 लाख, अगले साल 50 हजार सौलर पंप लगाएं जाएंगे जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट में की गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन के साथ विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया है। कृषि एवं पशुपालन को मजबूती, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर, महिलाओं के सशक्तिकरण तथा शहरी एवं ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना को साकार करता है। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ भाजपा सरकार को जनादेश दिया था, यह बजट उसी विश्वास को और मजबूत करने वाला है। राठौड़ ने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान बजट 2026—27 प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।

बजट निराशाजनक, विकास का रोडमैप गायब: गोविन्द सिंह डोटासरा

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए अपेक्षित वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना जल परियोजना और ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख तो किया गया, लेकिन इनके लिए कोई स्पष्ट बजट आवंटन नहीं हुआ। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रतिदिन आठ उद्योगों को भूमि आवंटन की बात कर रही है, लेकिन निवेश और रोजगार सृजन के आंकड़ों पर मौन है। शिक्षा क्षेत्र में 3768 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ की आवश्यकता बताई गई है, जबकि सरकार ने मात्र 550 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। उन्होंने किसानों के लिए गेहूं और बाजरे की एमएसपी पर बोनस की घोषणा न होने, नई भर्तियों की कमी और छात्रों को टैबलेट-लैपटॉप योजना का बजट घटाने को भी मुद्दा बनाया। डोटासरा ने कहा कि बजट में न नए महाविद्यालयों की घोषणा है, न अस्पतालों की। उनके अनुसार यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए निराशाजनक है और इसमें प्रदेश के विकास का स्पष्ट रोडमैप नजर नहीं आता।

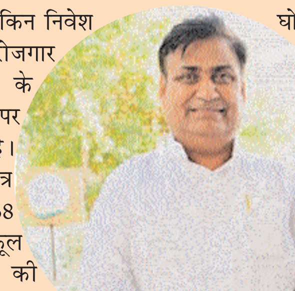

बजट पर गहलोत का हमला, बताया निराशाजनक

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखा हमला बोला है। गहलोत ने बजट को जनविरोधी और निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें किसी भी वर्ग के लिए ठोस राहत की घोषणा नहीं की गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी और श्वत्रष्टक्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का बजट में उल्लेख तक नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक बढ़ोतरी की घोषणा नहीं होने से 90 लाख से अधिक लाभार्थियों में निराशा है। युवाओं के लिए बड़ी सरकारी भर्तियों की घोषणा भी नहीं की गई, जबकि संविदा आधारित भर्ती पर जोर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाने की घोषणा पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले ही विवादों में रही है और राजस्थान लोक सेवा आयोग में रिक्त पद भरे बिना नई एजेंसी बनाना उचित नहीं है। इसके अलावा अन्नपूर्णा राशन किट योजना की बहाली नहीं होने और स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। कांग्रेस ने इसे जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला बजट बताया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साधा सरकार पर निशाना
'न विजन, न नीति, न नीयत... भाजपा का बजट विश्वासघाती'

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राज्य विधानसभा में पेश बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बजट को 'खोखला' और 'जनविरोधी' बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बजट न तो ठोस योजना प्रस्तुत करता है और न ही प्रदेश के विकास की स्पष्ट दिशा दिखाता है। जूली ने कहा कि पिछले दो बजटों में की गई 2718 घोषणाओं में से केवल 900 ही पूरी हुई हैं, जबकि 284 परियोजनाओं पर काम शुरू तक नहीं हो पाया। उन्होंने तंज

कसते हुए कहा, 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर सरकार घोषणाओं तक ही सीमित है, धरातल पर परिणाम नजर नहीं आ रहे। **जल जीवन मिशन पर सवाल**– नेता प्रतिपक्ष ने जल जीवन मिशन को सरकार की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि 45 लाख नल कनेक्शन देने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक केवल 14 लाख कनेक्शन ही दिए गए हैं। उनके अनुसार यह जनता के साथ विश्वासघात है।

वित्तीय प्रबंधन पर भी उठाए सवाल– जूली ने आरोप लगाया कि राज्य का राजस्व घाटा बढ़कर ?32,982 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि राजस्व प्राप्तियों में ?9,003 करोड़ की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय मोर्चे पर असफल रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है।

उन्होंने मशहूर शायर मिर्ज़ा ग़ालिब का शेर पढ़ते हुए कहा– 'उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आइना साफ़ करता रहा।' शिक्षा और ढांचे को लेकर चिंता नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के 42 हजार से अधिक जर्जर स्कूलों की स्थिति पर सरकार मौन है।

साथ ही 'नमो वन' और 'नमो नर्सरी' जैसी घोषणाओं को उन्होंने चापलूसी की राजनीति करार दिया। उन्होंने रिफाइनरी परियोजना में देरी और कुछ जिलों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार के पास ठोस रोडमैप का अभाव है।

भाजपा सरकार का बजट प्रदेश की जनता पर डंबल इंजन की सरकार का दोहरा कुठाराघात : पायलट

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए इसे प्रदेश की जनता पर डबल इंजन की सरकार का दोहरा कुठाराघात बताया है। पायलट ने कहा कि पहले केन्द्रीय बजट में भाजपा सरकार द्वारा राजस्थान की अनदेखी की गई और अब राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग की आशाओं पर पानी फेर दिया है। पायलट ने कहा कि झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और सरकार हफलनामे के माध्यम से यह स्वीकार भी किया था कि प्रदेश की स्कूलों की मरम्मत के लिए 21 हजार करोड़ रूपयों की आवश्यकता है। बावजूद इसके राज्य बजट में मात्र 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना यह बताता है कि राज्य सरकार को विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के चलते राजस्व घाटा बढ़ा है, सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा जिससे महंगाई बढ़ेगी। सरकार ने शब्दों के मायाजाल से अपनी दो वर्षों की नाकामी को छुपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के गत् वर्षों के बजट की भांति यह बजट भी धरातल पर उतरने वाला नहीं है।

पशुपालन एवं डेयरी सेक्टर को मजबूती देगा राज्य सरकार का बजट : जोराराम कुमावत

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित राजस्थान- 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। कुमावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट 'समृद्ध किसान, सशक्त पशुपालक और विकसित राजस्थान' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रावधानों से राज्य में पशुपालन क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

उन्होंने कहा कि बजट में पशुपालन, डेयरी मूल्य शृंखला, सहकारी निवेश को लेकर जो प्रोत्साहन दिए गए हैं, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। मंत्री ने इसे महिलाओं, छोटे किसानों और ग्रामीण गरीबों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान (विकसित भारत) के लिए एक निर्णायक कदम माना। कुमावत ने पशुपालन से किसानों की आय में 25 से 30 प्रतिशत योगदान को स्वीकारते हुए कहा कि इस क्षेत्र में उद्यमिता विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। **एनसीआर, यूपी व एमपी में सरस खोलेगा आउटलेट्स**— कुमावत का मानना है कि बजट में किए गए प्रावधान डेयरी सेक्टर को मजबूती तो देगें ही किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के साथ-साथ राज्य सरकार के 'विकसित प्रदेश के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह बजट डेयरी और पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए

2000 करोड़ के कोरपस फंड की घोषणा का स्वागत करते हुए, कहा कि सरस ब्रांड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए एनसीआर, उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के आउटलेट्स खोले जाएंगे।

इसके लिए 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। दुग्ध उत्पादन को बढावा देने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है।

संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ता ऐतिहासिक बजट : अविनाश गहलोत,

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य की दिशा में ठोस, निर्णायक और परिणामोन्मुखी कदम है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट न केवल वित्तीय प्रबंधन का दस्तावेज है, बल्कि यह प्रदेश के सर्वांगीण, समावेशी और संतुलित विकास का स्पष्ट रोडमैप भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस प्रकार सामाजिक न्याय, युवा सशक्तिकरण, महिला उत्थान, किसान कल्याण और गरीब वर्ग के जीवन स्तर में सुधार को बजट के केंद्र में रखा है, वह उनकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

'राज सवेरा' योजना के माध्यम से प्रदेश को नशामुक्त बनाने का संकल्प हो या घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू वर्ग के बच्चों के लिए 'स्कूल ऑन व्हील्स' जैसी अभिनव पहल—ये निर्णय समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना, युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले सुविधा तथा जिला मुख्यालयों के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान जैसी घोषणाएं प्रदेश में रोजगार, कौशल, उद्योग और आधारभूत संरचना को नई गति देंगी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन और कानून व्यवस्था जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई घोषणाओं से प्रदेश विकास के उच्चतम शिखर को छू सकेगा। यह बजट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी : के. के. विश्नोई

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के. के. विश्नोई ने राज्य बजट 2026-27 को औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का रोडमैप बताया है। विश्नोई ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से राज्य में नए लॉजिस्टिक हब की स्थापना, जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए 3,600 हेक्टेयर भूमि विकसित करने और रीको की डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी को जारी रखने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

इसमें वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का संकल्प तथा इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के उपाय बताए गए हैं जो डबल इंजन की सरकार लागू करेगी। उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियां लागू की गई हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपये में से 8 लाख करोड़ रुपये निवेश समझौते धरातल पर उतर गए हैं। इसके साथ ही, पिछले वर्ष हर दिन लगभग 8 उद्योगों को जमीन आवंटित की गई। साथ ही, औद्योगिक आधारभूत उन्नयन एवं विकास के लिए गत एक वर्ष में जो राशि खर्च की गई है, वो 50 वर्षों में सर्वाधिक है। निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निवेशकों और उद्योगों के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म के तहत 'एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक' के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियां देने की व्यवस्था की जाएगी। इस बजट में किए गए प्रावधानों से औद्योगिक विकास यह गति और मजबूत होगी। रिन्यूएबल एनर्जी, ई-व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन स्किलिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलैण्ड कंटेनर डिपो और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी।

दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि क्षेत्रों के लिए 590 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान : गौतम कुमार दक

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि वर्ष 2026-27 का राज्य बजट विकसित राजस्थान ञ्च 2047 के विज़न को ठोस आधार प्रदान करने वाला विकासोन्मुखी एवं सर्वस्पर्शी बजट है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा तथा इससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। दक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में युवा कल्याण, आधारभूत संरचना, अपराध नियंत्रण, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, कृषि एवं कृषक कल्याण, सहकारिता, उद्योग, और पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों को संतुलित प्राथमिकता दी गई है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई घोषणाएं राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की प्रतिबद्धता का परिचायक हैं। बजट में युवा, महिला, किसान एवं श्रमिक आदि सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बजट में सहकारी सेक्टर की मजबूती के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं, जिससे 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को बल मिलेगा। किसानों को आर्थिक चिन्ता से मुक्ति दिलाने के लिए आगामी वर्ष में 35 लाख कृषकों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाने का बजट में प्रावधान किया गया है।

बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और समग्र विकास का रोडमैप : चिकित्सा मंत्री

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत राज्य का वर्ष 2026—27 का बजट स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री सु दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट में महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी वर्गों के उत्थान एवं विकसित राजस्थान का दूरदर्शी विजन है। यह बजट आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बजट में वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिससे हर परिवार को नि:शुल्क उपचार का लाभ मिल सकेगा। जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता का अत्याधुनिक आईपीडी टावर स्थापित होने से शिशु एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार होगा। प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर — के संबद्ध अस्पतालों में 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृहों का निर्माण होने से मरीजों के परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खींवसर ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर स्थापित किए जाने की घोषणा से दवा वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुलभ बनेगी।सड़क दुर्घटना, प्रसूति एवं हार्ट अटैक जैसी आपात स्थितियों में त्वरित उपचार सुनिश्चित करने हेतु राज सुरक्षा योजना लागू की जाएगी, जिससे आपातकालीन चिकित्सा तंत्र और अधिक प्रभावी होगा। इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राज ममता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।

विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को साकार करेगा राज्य बजट, :जल संसाधन मंत्री

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य बजट को जनकल्याण, आधारभूत संचरना विकास और संसाधनों के सुनियोजित उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भविष्योन्मुखी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार रखा है। रावत ने बताया कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसमें जल संसाधन क्षेत्र के लिए विशेष घोषणाएं हुई हैं। ये प्रदेश में सिंचाई विस्तार, जल संरक्षण और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह बजट राज्य को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल लाने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया गया है। बुधवार को पेश बजट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। इससे शीघ्र ही परियोजना के कार्य शुरू हो सकेंगे। इसके पूर्ण होने पर सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित पूरे शेखावाटी अंचल को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सतत प्रयासों और केन्द्र सरकार के सहयोग से शेखावाटी क्षेत्र की तीन दशक पुरानी मांग अब साकार होने जा रही है।

युवा, किसान, महिलाओं और ग्रामीणों के लिए ऐतिहासिक बजट:: डॉ. किरोड़ी लाल

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राज्य का बजट 2026-27 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र को साकार करते हुए 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन को मूर्त रूप देने वाला है। यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, आत्मनिर्भर बनाने और अन्नदाता की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि यह बजट आमजन, कृषक, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से कृषि बजट में इस वर्ष 7.59 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। कृषि विकास, कृषक कल्याण और अन्नदाता की आय में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग, क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार हेतु वर्ष 2030 तक क्षेत्र को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिस पर 1 हजार 340 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिससे 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

साथ ही 50 हजार सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर 1,500 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्नत तकनीक को बढ़ावा देते हुए 200 करोड़ रुपये के अनुदान से 4 हजार किसानों के खेतों पर ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, लो टनल और प्लास्टिक मल्च स्थापित किए जाएंगे। उद्यानिकी विकास के तहत औषधीय पौधों, मसाला फसलों, फूलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत 160 करोड़ रुपये के अनुदान से 50 हजार किसानों को पावर टिलर, डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरो और रीपर जैसे एंटी उपलब्ध कराए जाएंगे। 96 करोड़ रुपये की लागत से 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देते हुए 8 हजार डिग्गियां, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और आगामी दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाएगा, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

नई घोषणाओं की बौछारों से सरकार के प्रति अविश्वास पैदा होगा :रामपाल जाट

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए बजट 2026-27 को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा है कि पिछले वर्ष के बजट की घोषणाएं तो पूरी हुई नहीं और फिर इस वर्ष के बजट में नई घोषणाओ की बौछारें की गई, जो सरकार के प्रति जनता में अविश्वास उत्पन्न करती बजट भाषण में अंग्रेजी शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग हुआ है, यह हिंदी भाषा का तो अपमान है ही, हिंदी भाषी जन के लिए समझ से बाहर है। यथा- कृषि उपज के दाम के लिए विपणन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बजट 2025- 26 में डीडवाना में परबतसर, अजमेर में रुपनगढ़, टोंक में बनेठा, जैतारण में बर मंडियो के निर्माण के लिए घोषणा की गई थी किंतु इनमें से एक भी स्थान पर भूमि आवंटन एवं निर्माण का काम आरंभ नहीं हुआ। जाट ने कहा कि कोटा की भामाशाह तथा बारां मंडियों के विस्तार के लिए भी घोषणा की गई थी किंतु वह भी अभी तक आरंभ नहीं हुई। सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों की घोषणा भी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। बजट 2024 -25 में मांगते ही कनेक्शन देने की दिशा में 31 मार्च 2024 तक के लंबित कनेक्शन में से 1,45000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा अधूरी है। इसी प्रकार वर्ष 2025- 26 के बजट में 50,000 कृषि कनेक्शन देने की स्थिति भी अधूरी है, अभी तक 2022, 2023 एवं 2024 के कृषि कनेक्शन भी लंबित चल रहे हैं।

विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को साकार करने वाला सर्वस्पर्शी बजट : सीपी जोशी

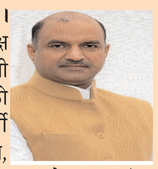

चित्तौड़गढ़, (हुक्मनामा समाचार)। चित्तौड़गढ़ सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार द्वारा वित्त मंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट को जनकल्याणकारी, विकासोन्मुखी एवं दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 'सर्व सुखाय, सर्व हिताय' की भावना के अनुरूप हर वर्ग का ध्यान रखने वाला सांसद सीपी जोशी ने कहा कि बजट में 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास, 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ बनाने, पेयजल परियोजनाओं के लिए 24 हजार करोड़ के वर्क ऑर्डर जारी करने, एक साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन जारी करने, 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ने, 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने, 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाने, सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने, चित्तौड़गढ़ में कुंभा पार्क डेवलप करने के लिए 31 करोड़ की घोषणा हुई है। सांसद सीपी जोशी ने कहा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर सेंटर खोले जाने, एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करने, प्रदेश के कॉलेजों में नए संकाय खोलने, सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज/अनुदान दिए जाने, जलवायु नीति और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ के निवेश का रोडमैप तैयार करने, लखपति दीदी योजना में कर्ज की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख करने, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित करने, प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए 225 करोड़ रूपये का प्रावधान।

'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से प्रेरित राजस्थान बजट :अरुण चतुर्वेदी

350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

जयपुर (हुक्मनामा समाचार)। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026-27 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भावना से प्रेरित एक समावेशी और दूरदर्शी बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और 'सिटीजन फर्स्ट' के संकल्प के अनुरूप प्रदेश को विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में तेजी से अग्रसर करेगा। चतुर्वेदी ने कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों गरीब, युवा, अन्नदाता किसान, नारी, मजदूर एवं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास' की मूल भावना इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, उद्योगों के विस्तार, कृषि एवं पशुपालन के सशक्तीकरण और निवेश प्रोत्साहन से प्रदेश में व्यापक रोजगार सृजन होगा। वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार की मजबूत आर्थिक दृष्टि को दर्शाता है। वित्त आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कृषि प्रधान राजस्थान में किसानों और ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है,।

एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं राष्ट्रवादी विचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय

बूंदी (हुक्मनामा समाचार)। भाजपा जिला कार्यालय पर बुधवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी कार्यक्रम जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ । कार्यक्रम से पूर्व सभी पदाधिकारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित और श्रद्धांजलि अर्पित की । भाजपा प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि मुख्य वक्ता पूर्व जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी बिल्या ने पंडित उपाध्याय के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपाध्याय भारतीय जन संघ के संस्थापक और एकात्म , मानववाद के प्रणेता एवं राष्ट्रवादी विचारक थे । उन्होंने कहा कि उपाध्याय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कानूनी मंत्री भी रहे । उन्होंने एकात्म मानववाद का नारा देश की जनता को दिया उपाध्याय संगठन की रीति नीति के साथ संगठन को मजबूती देते हुए आगे बढ़ाया । उन्होंने कहा कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पंडित उपाध्याय की हत्या हो गई थी । वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार उनके राष्ट्रवादी विचारधारा के पद चिन्हों पर चल रही है। हम सभी को उनके बताएं मार्ग पर चलते हुए संगठन को आगे बढ़ाना है । बिल्या मैं कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक शिष्य थे । संगोष्ठी में जिला अध्यक्ष मीणा व कांति नागर ने भी अपने विचार व्यक्त किये । जिला महामंत्री संजय लाठी , राधेश्याम गुर्जर , एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मीणा ,ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री राधेश्याम बैरागी, शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रंगी , कहार केवट समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरिनंदन कहार, कोषाध्यक्ष सुनील जैथलिया, पूर्व पार्षद राजेश शेरगड़िया , चुन्नीलाल चंदोलिया भी मंचासीन रहे । इस मौके पर जिला पदाधिकारी , जिले के सभी मंडलों के अध्यक्ष , महामंत्री , मोर्चा व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन जिला महामंत्री योगेंद्र श्रंगी ने किया ।

बूंदी शहर में हुड को लोन के प्लांन कार्यो को ही बजट में अंकित कर दिया

बूंदी (हुक्मनामा समाचार)। विधायक हरिमोहन शर्मा ने यह भी बताया कि बजट के अंतर्गत बूंदी शहर में हुडको लोन के प्लान में प्रस्तावित जो विकास कार्य थे उन्हीं कार्यों को अनुमानित लागत मानकर कर बजट में अंकित कर दिया। जिसका कोई डीपीआर और कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। बूंदी की लगातार उपेक्षा किए जाने पर मैं सरकार की घोर निंदा करये हुए कहा कि राजस्थान का 2026-27 का बजट 'दिशाहीन ', 'निराशाजनक' और 'खोखली घोषणाओं' वाला है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

बजट 2026 डीडवाना कुचामन को मिली प्रशासनिक भवनों और विकास कार्यों की सौगात

डीडवाना (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान की भजनलाल सरकार के तीसरे बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने नए जिलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है।डीडवाना-कुचामन जिले के लिए यह बजट प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, सड़क कनेक्टिविटी और सामाजिक कल्याण के नजरिए से उम्मीदों भरा रहा है। जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय के निर्माण की घोषणा के साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करोड़ों के विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।?लंबे समय से जिला मुख्यालय पर स्थाई कार्यालयों की कमी महसूस की जा रही थी। बजट में डीडवाना में मिनी सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों के लिए भव्य भवनों के निर्माण हेतु बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, जिला मुख्यालय पर जिला अभियोजन भवन कार्यालय का निर्माण भी होगा, जिससे न्यायिक कार्यों में सुगमता आएगी।?जिले के वंचित और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए 'स्कूल ऑन व्हील्स' की अनूठी पहल की गई है। यह चलता-फिरता स्कूल उन बच्चों तक शिक्षा पहुँचाएगा जो संसाधनों की कमी के कारण स्कूल नहीं जा पाते। साथ ही, जिला स्तर पर 'इंस्टिट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट' के जरिए युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। जिला अस्पताल में नशे की लत छुड़वाने के लिए विशेष केंद्र की स्थापना होगी।मानसिक रोगियों के उपचार और पुनर्वास के लिए जिले में समर्पित केंद्र खोला जाएगा। नावां क्षेत्र की रेवासा दलेलपुरा ग्राम पंचायत में नया पशु चिकित्सा उप-केंद्र खुलेगा।?सड़क निर्माण के मामले में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बजट मिला है:?मकराना: माताभर दिल्ली चौराहा से बाईपास और गच्छीपुरा वाया बेसरोली तक 23.5 किमी सड़क के लिए 22.70 करोड़ रुपये। नावां: श्यामगढ़ से कांटिया बरजन तक 15 किमी सड़क हेतु 6.75 करोड़ रुपये।लाडनूं/डीडवाना निम्बी जोधा से मालगांव-सिलनवाद तक 25 किमी सड़क के लिए 5 करोड़ रुपये से बनेगी।परबतसर में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।जिले की सुरक्षा निगरानी को हाईटेक बनाने के लिए अभय कमांड सेंटर की स्थापना होगी।कुचामन सिटी में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (ह्ड्ढ ,ष्ह्र) न्यायालय खुलेगा।?पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले में 'उन्नत नमो नर्सरी' स्थापित की जाएगी, जहाँ से आमजन को उच्च गुणवत्ता के पौधे मिल सकेंगे। वहीं, स्वच्छता के मोर्चे पर शहर की जल निकासी समस्या को हल करने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान को बजट में शामिल किया गया है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में खड़ी पावा में 33/11 केवी का जीएसएस बनेगा।

डीडवाना के समग्र विकास हेतु बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएँ: जोधा

डीडवाना (हुक्मनामा समाचार)। राज्य सरकार के बजट पेश को भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने सही बताया है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए डीडवाना क्षेत्र के समग्र एवं सतत विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ये निर्णय क्षेत्र के आधारभूत ढाँचे, प्रशासनिक सुदृढ़ता एवं सामाजिक सुरक्षा को नई गति प्रदान करेंगे। डीडवाना के विकास हेतु की गई प्रमुख घोषणाएँ इस प्रकार हैं। डीडवाना में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि आवंटन की घोषणा खुड़ी पावा में 33/11 केवी जीएसएस (ग्रिड सब-स्टेशन) की स्थापना की घोषणा डीडवाना में अभय कमांड सेंटर की स्थापना एवं आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु 40 करोड़ रुपये की घोषणा डीडवाना में एससी/एसटी वृत्त कार्यालय की स्थापना डीडवाना में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की स्थापना डीडवाना शहर में विभिन्न नवीन सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु बजट आवंटन जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना डीडवाना में नॉन-पेचेबल सड़कों के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का आवंटन मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण हेतु लगभग 5 करोड़ रुपये का प्रावधान डीडवाना में 25 बच्चों की क्षमता वाला बालगृह खोले जाने की घोषणा।

राजस्थान सरकार के पिछले बजट में कोटा शहर के लिए की गई घोषणाएं

धरातल पर नहीं उतरी,आज फिर नई घोषणाएं से जनता को कब तक गुमराह करते रहोंगे :राखी गौतम

कोटा (हुक्मनामा समाचार)। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा दिए गए आम बजट पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि आम बजट आम गरीब जन विरोधी है बेहद निराशा जनक दिशाहीन, व्यापारी,मध्यम वर्ग,मंहगाई को बढ़ाने वाला गरीब जन विरोधी बताया है ।गौतम ने बताया कि पिछले बजट को देखते हुए कहा कि राजस्थान के बजट 2025 - 26 में कोटा के लिए भामाशाह मंडी के विस्तार की घोषणा की गई थी लेकिन मंडी का विस्तार केवल बजट के कागजों तक ही सीमित रह गया । कोटा में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी लेकिन बजट आए एक साल होने में आ गया सचिवालय निर्माण हेतु एक ईंट तक नहीं रखी गई ।कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की घोषणा थी जो केवल घोषणा ही बन कर रह गई ।कोटा जिले में पैरा स्पोर्ट्स के लिए सोशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई थी सरकार का जवाब है कि बजट नहीं आया । घोषणाएं केवल कागजों पर ही रह गई धरातल पर नहीं उतरी ।गौतम ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आखिर घोषणाएं करनी ही क्यों है जब पूरा नहीं कर सकते तो क्या केवल अखबारों के छपने के लिए जनता को गुमराह करते हो गौतम ने वर्तमान बजट को को सुनकर कहा की कोटा जिले के साथ तो पिछले बजट की तरह सौतेलापन किया गया है ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर बांसखेड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन हिंदू एकता ओर समरसता का दिया गया संदेश

पिड़ावा (हुक्मनामा समाचार)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पिड़ावा खंड के बांसखेड़ी मंडल में एक भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मंडल के सभी गांवों से बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिलाओं ने सहभागिता कर हिंदू एकता और सांस्कृतिक चेतना का परिचय दिया।कार्यक्रम मां सरस्वती की पूजा ओर दीप प्रज्वलन के साथ भजनों ओर देश भक्ति के गीतों पर आनंद लेते हुए सभी ने विशाल शोभा यात्रा निकालीखंड महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख राजपाल सिंह ने बताया कि मुख्य वक्ता के रूप में अपने उद्बोधन में कहा कि संघ के 100 वर्ष की यात्रा हिंदू समाज के संगठन, सेवा संस्कार, ओर सामाजिक समरसता पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्य की बात की उन्होंने समाज से संगठित होकर सनातन संस्कृति, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए निरंतर जागृत रहने ओर संघ के पंच परिवर्तन के पालन का आह्वान करते हुए वक्ता ने कहा कि हिंदू समाज की जागृति ही राष्ट्र की मजबूती की आधारशिला है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कार, परंपरा और संस्कृति पर गर्व करते हुए समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए ओर हिंदू समाज में समरसता के साथ आगे बढ़ने का आह्वाहन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष कालू सिंह, मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित रुक्मा कुंवर ओर मुख्य अतिथियों का स्वागत तरवर सिंह, लाल सिंह, भारत सिंह, पीरु सिंह सहित अन्य ने किया। समापन भारत माता कि आरती, ओर सामूहिक अल्पाहार तथा प्रसाद वितरण के साथ किया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत कृषि आदान विक्रेताओं का सघन निरीक्षण

चित्तौड़गढ़ (हुक्मनामा समाचार)। अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड भीलवाड़ा श्री इन्द्र सिंह संचेती एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद चित्तौड़गढ़ डॉ. शंकर लाल जाट के निर्देशन में जिले में विशेष गुण नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कृषि आदान विक्रेताओं का सघन निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूने लिए गए। इस क्रम में लक्ष्मी धाकड़ बीज भंडार शंभूपुरा, श्रीश्याम बीज भंडार शंभूपुरा, भंडारी मशीनरी मार्ट चित्तौड़गढ़, श्री गणपति फर्टिलाइजर्स गोराजी का निम्बाहेड़ा, बालाजी बीज भंडार कनेरा, श्रीराम कृषि सेवा केन्द्र कनेरा, कोठारी ट्रेडर्स बस्सी सहित विभिन्न विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया गया।निरीक्षण दल में सहायक निदेशक कृषि (मुख्यालय) चित्तौड़गढ़ मुकेश कुमार धाकड़, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अंशु चौधरी, कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) ज्योति प्रकाश सिरोया, कृषि अधिकारी (मिशन) रामजस खटीक, कृषि अधिकारी (सामान्य) गोपाल लाल धाकड़ एवं कृषि अधिकारी (फसल) कपासन श्रप्रशांत कुमार शामिल रहे।अभियान के दौरान उर्वरक के 6 एवं कीटनाशी के 10 नमूने, कुल 16 नमूने गुणवत्ता परीक्षण हेतु आहरित किए गए। विभागीय नियमों की अवहेलना पाए जाने पर 5 कृषि आदान विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. शंकर लाल जाट ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि कृषकों को कृषि आदान विक्रय करते समय पक्का बिल अवश्य दिया जाए, दुकानों पर मूल्य सूची प्रदर्शित रखी जाए, स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखा जाए तथा उपलब्ध सभी आदानों को अनुज्ञापत्र में सम्मिलित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पीसांगन पंजाब नेशनल बैंक ने किया वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन

मागलियावास (हुक्मनामा समाचार)। भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋक्च्ढ्ढ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, पीसांगन शाखा द्वारा एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं, सरकारी बीमा योजनाओं, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा एवं बचत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक हीरदास सहित बैंक स्टाफ शिव प्रकाश बैरवा, शांति लाल भाटी, दिनेश कुमावत, किशन सिंह,कार्तिक कुमार,विधि शर्मा एवं ग्राहकगण उपस्थित रहे।इस अवसर स्व निम्बा राम के निधन उपरांत उनके खाते से संबंधित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (क्क्रूस्क्चङ्घ) के अंतर्गत 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) की दावा राशि का निपटान नियमानुसार किया गया। उक्त राशि का चेक प्रतिरूप नामांकित अभिभाषी (ह्रश्वद्बठ्ठद्गद्ग) शांति देवी को प्रदान किया गया।

बजट पर प्रतिक्रिया बजट को बताया सकारात्मक

मौलासर (हुक्मनामा समाचार)। सामाजिक कार्यकर्ता गुमान सिंह गोगावत, नूवा राजस्थान बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए नूवा के सामाजिक कार्यकर्ता गुमान सिंह गोगावत ने कहा कि यह बजट ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। अस्पतालों में फायर सेफ्टी, विश्रामगृह और मोक्ष वाहिनी सेवा जैसी घोषणाएं आमजन के लिए राहतकारी हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा बढ़ाने, लखपति दीदी योजना के विस्तार और युवाओं को बिना ब्याज ऋण देने के फैसले का स्वागत किया।गोगावत ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अमृत पोषण वाटिका, नए पेयजल कनेक्शन और ऊर्जा क्षेत्र में सोलर पार्क जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी। उन्होंने बजट को 'विकासोन्मुख और जनहितकारी' बताया।

सूअरों से किसान परेशान फसलों के नुकसान पर उपखण्ड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने किया मौके पर निरीक्षण

थांवला (हुक्मनामा समाचार)। थांवला के निकटवर्ती ग्राम सूदवाड़, गुढ़ा जोधा एवं भेरूंदा में सूअरों के झुंड द्वारा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए रियांबड़ी उपखण्ड अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर खेतों की स्थिति का जायजा लिया और किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया।निरीक्षण के दौरान किसानों ने बताया कि सुवरों के झुंड आए दिन खेतों में घुसकर खड़ी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। इससे उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर रहा है और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई किसानों ने यह भी कहा कि फसल बर्बादी के कारण उनके परिवार की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है।मौके पर स्थिति का अवलोकन करने के बाद उपखण्ड अधिकारी ने क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेड़ता को निर्देश दिए कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए सर्वे कराया जाए तथा सुवरों की बढ़ती संख्या और उनके आवागमन के कारणों का पता लगाया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को राहत दिलाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।सूर्यकांत शर्मा ने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जल्द ही प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर लागू की जाएगी।

सीएचसी भवन निर्माण में भारी लापरवाही , समय सीमा खत्म होने के दो माह बाद भी काम अधूरा

जवाजा (हुक्मनामा समाचार)। क्षेत्र के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दावे फिलहाल कागजों और अधूरे निर्माण के बीच फंसे नजर आ रहे हैं। जवाजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नए भवन का निर्माण कार्य कछुआ गति से चलने के कारण आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय लापरवाही का आलम यह है कि जिस कार्य को दिसंबर माह में पूरा हो जाना चाहिए था, वह समय सीमा बीतने के दो माह बाद भी अधर में लटका हुआ है।दिसंबर की डेडलाइन हुई फेलजवाजा चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, निर्माण एजेंसी को दिसंबर माह तक भवन का कार्य पूर्ण कर हैंडओवर करना था। लेकिन अब फरवरी का महीना भी आधा बीत चुका है और जमीनी हकीकत यह है कि प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार ने प्रशासन और ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।सड़क लेवल और मिट्टी भराव का काम अटकानिर्माण में देरी का एक मुख्य कारण परिसर में मिट्टी के भराव का काम न होना बताया जा रहा है। भवन को मुख्य सड़क के लेवल तक लाने के लिए भारी मात्रा में मिट्टी डालना अनिवार्य है। जब तक मिट्टी भराव और लेवलिंग का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक भवन का बाहरी बुनियादी ढांचा उपयोग के लायक नहीं बन पाएगा। इस देरी के कारण अस्पताल में नई मशीनों और चिकित्सा उपकरणों को शिफ्ट करने का काम भी रुका हुआ है। मरीजों की बढ़ रही मुश्किलेंवर्तमान में पुराने ढांचे में चल रही चिकित्सा सेवाओं के कारण मरीजों और स्टाफ दोनों को परेशानी हो रही है।

नए भवन में आधुनिक सुविधाओं और अधिक बेड की उम्मीद थी, जो अब समय पर पूरी होती नहीं दिख रही। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य इसी गति से चलता रहा, तो इसे पूरा होने में अभी कई और महीने लग सकते हैं।अधिकारियों का पक्षचिकित्सा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। विभाग का कहना ह कि ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द भवन को जनता के लिए समर्पित किया जा सके। हालांकि, निर्माण एजेंसी की ओर से देरी का कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

लगातार तीसरे बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र को मिली कई बड़ी सौगातें

सरकार का बजट राजस्थान के सर्वजन हिताय की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट : विधायक कृपलानी

निम्बाहेड़ा (हुक्मनामा सामाचार)। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार के वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत आम बजट को पूर्व यूडीएच मंत्री एवं निम्बाहेड़ा विधायक चंद कृपलानी ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम बताया है। -बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृपलानी ने कहा कि यह बजट सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना को साकार करने वाला है, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, श्रमिकों एवं उद्योग जगत सहित प्रत्येक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश की विकास यात्रा को गति देने का कार्य किया है। विधायक कृपलानी ने कहा कि युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार, रोजगार के नए अवसरों के सृजन तथा पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से युवा शक्ति को सशक्त आधार प्रदान किया जाएगा। किसानों के हित में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, कृषि अनुदान, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा उत्पादन वृद्धि के प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार एवं बुजुर्गों के कल्याण हेतु किए गए प्रावधानों को संवेदनशील पहल बताते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री मति दीया कुमारी द्वारा पूर्व यूडीएच मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक चंद कृपलानी की अनुशंसा पर निम्बाहेड़ा में बहुप्रतिक्षित एनडीपीसी कोर्ट की स्वीकृति के साथ ही निम्बाहेड़ा के रसूलपुरा जीएसएस 220 जीएसएस की सौगात मिली है। इसके साथ ही विधायक कृपलानी की अनुशंसा पर करताना फाटक से व्हाया बडौली घाटा होते हुए अरनोदा-मांगरोल मार्ग तक करीब 8.50 किलोमीटर लम्बी सड़क का करीब 4 करोड़ की लागत से सड़क का नवीनीकरण कार्य, जाखम बांध परियोजना के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़) एवं छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़) कस्बे व ब्लॉक में लघु परियोजना से लाभांवित ग्रामों को क्रह्वद्यद्ध ड्ढड्डह्लद्गहम् उपलब्ध करवाने की डीपीआर के लिए 1 करोड़ 37 लाख रूपये स्वीकृत तथा नगर परिषद निम्बाहेड़ा के रानीखेड़ा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाने की स्वीकृति जारी हुई है।

राज्य सरकार के बजट में डीडवाना को नहीं मिला कुछ भी लोगों में हुई निराशा

डीडवाना (हुक्मनामा सामाचार)। उपखंड क्षेत्र में आज राज्य सरकार के द्वारा बजट पेश में कुछ भी नहीं मिला है जिसको लेकर आमजन में भारी नाराजगी है और निराशाजनक भी है लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पर प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ता गुमान सिंह गोगावत, नूवा* राजस्थान बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए नूवा के सामाजिक कार्यकर्ता गुमानसिंह गोगावत ने कहा कि यह बजट ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।अस्पतालों में फायर सेफ्टी विश्रामगृह और मोक्ष वाहिनी सेवा जैसी घोषणाएं आमजन के लिए राहतकारी हैं।उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा बढ़ाने लखपति दीदी योजना के विस्तार और युवाओं को बिना ब्याज ऋण देने के फैसले का स्वागत किया।गोगावत ने कहा कि ग्राम पंचायतों में अमृत पोषण वाटिका, नए पेयजल कनेक्शन और ऊर्जा क्षेत्र में सोलर पार्क जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी। उन्होंने बजट को विकासोन्मुख और जनहितकारी बताया। बजट को लेकर लोकेश पारीक ने कहा भाजपा सरकार का यह बजट मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विकास दृष्टि का प्रतीक है।हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प इसमें साफ दिखाई देता है।रोजगार निवेश और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर प्रदेश की प्रगति को गति देगा।राजस्थान अब तेज़ विकास की ओर निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

पूर्व विधायक चेतन डूडी ने बजट को लेकर पोस्ट कर कहा डीडवाना का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।बजट 2026 में डीडवाना का नाम तक नहीं आया विकास ग़ायब। मोहम्मद इरफान रंगरेज जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस नागौर डीडवाना कुचामन ने कहा राजस्थान का यह बजट केन्द्रीय बजट की तरह ही आमजन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। प्रदेश का युवा लंबे समय से रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और स्थायी अवसरों की आस लगाए बैठा था, डीडवाना को सीवरेज गंदा पानी का समाधान कोई ठोस घोषणा नहीं हुई इसमें डीडवाना की जनता में निराशा है।

बारां में तीन दिवसीय पासपोर्ट कैम्प प्रारंभ

बारां (हुक्मनामा सामाचार)। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा की ओर से जिले में मोबाइल वेन के माध्यम से तीन दिवसीय पासपोर्ट कैम्प का आयोजन बुधवार से जिला कलक्ट्रेट परिसर में प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कोटा यशवंत माठे, एडीएम भंवरलाल जनागल और एसडीएम विश्वजीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर मोबाइल कैम्प का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी माठे ने बताया के विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट सेवा आपके द्वार योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके द्वारा मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से बारां जिले एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। माठे ने बताया के यह कैम्प 11 से 13 फरवरी तक कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया जा रहा है तथा प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आवेदकों की मांग को देखकर यह कैम्प प्रतिमाह आयोजित किया जा सकता है। माठे ने यह भी कहा के पासपोर्ट कार्यालय कोटा में अब तक 2 लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं जिसमें करीब 54000 ई-पासपोर्ट भी हैं और निरंतर बेहतर सेवा के प्रति वचनबद्ध हैं। एडीएम जनागल और एसडीएम सिंह ने माठे और उनकी टीम का धन्यवाद दिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।

बजट 2026-27: भीलवाड़ा को सड़कों व पुलों की सौगात, करोड़ों के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

भीलवाड़ा (हुक्मनामा सामाचार)।राज्य बजट 2026-27 में भीलवाड़ा जिले को सड़क व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में जिले की विभिन्न सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण व पुल निर्माण कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के प्रावधान किए गए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। ??? 98 करोड़ से सुदृढ़ होगी मंडल-शाहपुरा सड़कबजट में मंडल-शाहपुरा सड़क (40 किमी) के सुदृढ़ीकरण के लिए 98 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में था, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जहाजपुर व मांडलगढ़ क्षेत्र को भी राहत धनवाड़ा चौराहा से चंवलिया पार्श्वनाथ से राजगढ़ तक (जहाजपुर) 13 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण। भीलवाड़ा से देवगढ़ मार्ग (मांडल क्षेत्र) के 4.60 किमी हिस्से के सुदृढ़ीकरण पर 4.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बड़लियास से भावनपुरा (मांडलगढ़) सड़क निर्माण पर 2.40 करोड़ रुपये स्वीकृत। पुल निर्माण पर भी फोकस जिले में विभिन्न स्थानों पर पुल निर्माण व मरम्मत के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है— कोठारी नदी पर लड़की से सरवड़ी के बीच पुल निर्माण - 4 करोड़ रुपये। सुरास से मालीखेड़ा मार्ग पर कोठारी नदी पर पुल - 7.20 करोड़ रुपये। इन परियोजनाओं से बरसात के दौरान आवागमन बाधित होने की समस्या से राहत मिलेगी। ग्रामीण संपर्क मार्गों को मजबूतीग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सड़कों के उन्नयन से किसानों व ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट में नॉन-पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ भी भीलवाड़ा को मिलेगा। विकास को मिलेगी रफ्तार विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क व पुल परियोजनाओं से भीलवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्रों, खासकर टेक्सटाइल हब, को सीधा फायदा होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से परिवहन लागत घटेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जिले के जनप्रतिनिधियों ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए इसे भीलवाड़ा के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि स्वीकृत परियोजनाएं धरातल पर कितनी तेजी से उतरती हैं।

नाइलिट पाली द्वारा पहला जॉब फेयर आयोजित; 50 से अधिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

केकड़ी/पाली(हुक्मनामा सामाचार)। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी नाइलिट पाली केंद्र, जो कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, ने अपने महावीर नगर परिसर, पाली में पहला जॉब फेयर सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह आयोजन मारवाड़ क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस जॉब फेयर में देश की 10 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से पेटीएम,एक्सिस बैंक,वी5 ग्लोबल,पुखराज हेल्थ केयर,सफारी मेन्युफेक्चरिंग ली.स्पेक्ट्रम टेलेंट मैनेजमेंट लि.टिमलेस सर्विसेज,इंजीनियस एचआर सॉल्यूशन,राधे अमृत क्रियेशन्स,सिद्धि इंफोटेक व आमधने प्रा.लि. शामिल रहीं। उद्योग विशेषज्ञों द्वारा इंटरव्यू, भर्ती प्रक्रिया और करियर मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से उम्मीदवारों को काफी लाभ मिला।इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेम राज नोगिया (टीडीएम बीएसएनएल पाली), संदीप सिंह (एजीएम बीएसएनएल पाली) तथा सुनील राजपुरोहित (मैनेजर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन किया और डिजिटल अर्थव्यवस्था में कुशल मानव संसाधन की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. संजीव कुमार गुप्ता, कार्यकारी निदेशक, नाइलिट राजस्थान ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और आय के अवसर सृजित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि नाइलिट पाली में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, तथा पायथन जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉ. गुप्ता ने यह भी बताया कि नाइलिट के पास आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 50 से अधिक रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का व्यापक विकल्प है। ये सभी कोर्स प्रोजेक्ट आधारित और परिणामोन्मुखी शिक्षण पद्धति पर आधारित हैं। साथ ही, विद्यार्थियों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जॉब फेयर केवल शुरुआत है और ह्लश्वस्रुञ्ज आगे भी नियमित रूप से ऐसे प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करेगा, जिससे न केवल नाइलिट के विद्यार्थी बल्कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य संस्थानों के पासआउट छात्र भी लाभान्वित हो सकें।

जनगणना-2027 के सफल क्रियान्वयन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

चित्तौड़गढ़ (हुक्मनामा सामाचार)।आगामी भारत की जनगणना-2027 के राष्ट्रीय महाअभियान के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित सांख्यिकी कार्यालय में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता उप जिला जनगणना अधिकारी एवं उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग शबनम खोरवाल ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना निदेशालय से आए सांख्यिकी अधिकारी महेन्द्र कुमार मीणा एवं द्विपेंन्द्र धाभाई द्वारा जिले के चार्ज कार्यालयों (तहसील/नगर क्षेत्र) से नियुक्त नियमित सहायकों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर खोरवाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना-2027 पूरी तरह से पेपरलेस एवं डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। जनगणना देश के विकास की आधारशिला है, अतः इसमें संलग्न प्रत्येक कार्मिक का दायित्व है कि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करे। प्रशिक्षण के दौरान पीपीटी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनगणना कार्य से संबंधित ष्टरूरू पोर्टल, ॥स्रुष्ट वेब एप्लीकेशन एवं ॥स्रु मोबाइल ऐप का गहन तकनीकी एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही चार्ज स्तर पर संपादित किए जाने वाले जनगणना संबंधी कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि जनगणना-2027 राष्ट्रीय महत्व का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसकी गुणवत्ता सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले आंकड़ों की शुद्धता से जुड़ी होती है। उन्होंने जानकारी दी कि जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य स्व-गणना के माध्यम से 1 मई से 15 मई 2027 तक तथा फील्ड कार्य 16 मई से 14 जून 2027 तक संपन्न किया जाएगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर गठित जनगणना सेल के अधिकारीगण/सहायक अधिकारी तथा प्रत्येक चार्ज कार्यालय से नियुक्त जनगणना लिपिक एवं नियमित सहायकों ने भाग लिया।

तुलसी की लिखी लग्न पत्रिका,बारात बागोर से आएगी

भीलवाड़ा (हुक्मनामा सामाचार)। माली समाज विकास सेवा संस्थान पुर के तत्वावधान में चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन पुर स्थित घाटी के हनुमानजी परिसर में 19 फरवरी 2026 को सम्पन्न किया जाएगा । माली समाज के चुतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन कि शुरुआत आज बुधवार को तुलसी संग सालगराम जी के लग्न से की गई। माली समाज विकास सेवा संस्थान पुर के अध्यक्ष भैरूलाल माली ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को फुलेरादोज पर आयोजित होने वाले माली समाज के चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन में भगवान सालगराम जी संग तुलसी विवाह भी सम्पन्न किया जाएगा। इसी कड़ी में आज बुधवार को बागोर माली समाज के पंच पटेलो ने तुलसी विवाह के तहत आज विधि-विधान से चुनरी दस्तुर किया गया, तत्पश्चात् पं. अशोक शर्मा के सानिध्य में लग्न पत्रिका भी लिखी गई। उपस्थित सभी समाजजनों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में आने की निमंत्रण पत्रिका भी वितरित की गई। अब तक इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 17 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। विवाह समिति का लक्ष्य 21 जोड़ो का विवाह कराना है। इस ओर समाजजन हर तरह से प्रयासरत है। संस्था अध्यक्ष ने समाज से अपील की है कि इस सम्मेलन में सभी समाजबंधु एकजुट होकर तन-मन-धन से विवाह समिति को भरपूर सहयोग करें, ताकि इस आयोजन को भव्यता प्रदान की जा सके।इस अवसर पर सामूहिक विवाह समिति के सचिव शंकरलाल गोयल, संरक्षक रामस्वरूप माली, तोताराम सांखला, कैलाश नुईवाल, जगदीश ढिबरिया, बंशीलाल माली, प्रभुलाल नुईवाल, बंशीलाल कनवासिया, रामेश्वर लाल माली, नानूराम गोयल, देवालाल ढिबरिया, , नारायण कनवासिया, कालू माली, लाल चंद गोयल, महावीर ढिबरिया, माली महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली, जिला महामंत्री सत्यनारायण माली, युवा महासभा जिला अध्यक्ष उदयलाल माली, सोशल मीडिया प्रभारी रोशन गढ़वाल, राजकुमार गोयल, सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित थे।

बाइक-ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में युवक की मौत

कुचेरा (हुक्मनामा सामाचार)। शहर के अड़वड़-कसनाऊ रोड पर बुधवार शाम करीब छह बजे एक बाइक और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के चालक सुरेश छाबा और ईएमटी पूनमचंद टाक मौके पर पहुंचे तथा घायल को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान फडोद निवासी इरफान पुत्र सदीक धोबी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर कुचेरा पुलिस के एएसआई केसाराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कुचेरा मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।

जारोड़ा-बुटाटी धाम सड़क निर्माण को 4.21 करोड़ की स्वीकृति, क्षेत्र में खुशी

कुचेरा (हुक्मनामा सामाचार)। जारोड़ा से बुटाटी धाम तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 21 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके स्वीकृत होते ही लोगों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

स्विगी और रॉबिन हुड आर्मी का ष्विंटर वंडरलैंडष् अभियान

कोटा (हुक्मनामा सामाचार)।भारत के अग्रणी ऑन.डिमांड कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म स्विगी ने रॉबिन हुड आर्मी के साथ मिलकर ष्विंटर वंडरलैंडष् अभियान आयोजित किया। यह एक दिल को छू लेने वाली सर्दियों की पहल थीए जिसका उद्देश्य भारत भर में जरूरतमंद और कमजोर समुदायों तक गर्माहटए देखभाल और पोषण पहुंचाना था। यह अभियान सर्दियों के चरम समय में सबसे अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को ताजा तैयार भोजन उपलब्ध कराने पर केंद्रित था और इसे भारत के 14 राज्यों के 56 शहरों में चलाया गया।

राजस्थान में तापमान गिरने के साथ हीए स्विगी और रॉबिन हुड आर्मी ने बीकानेरए कोटाए कोटपुतली सहित अन्य स्थानों पर खुले स्लम में रहने वाले बच्चोंए अनाथालयों के निवासियोंए सड़कों पर रहने वाले लोगों और अन्य वंचित समुदायों को पूरीए सब्जी और मिठाई सहित 200 ताजा तैयार भोजन वितरित किए। स्विगी के सहयोग सेए रॉबिन हुड आर्मी के स्वयंसेवकों ने एक साथ कई शहरों में भोजन वितरण का आयोजन किया । स्विगी फूड मार्केटप्लेस के चीफ बिजनेस ऑफिसर सिद्धार्थ भाकू ने कहाए शिस्वगी में हम हमेशा अपनी पूरे भारत में उपस्थितिए बड़े पैमाने और संसाधनों का उपयोग खुशियां फैलाने के लिए करते आए हैं। रॉबिन हुड आर्मी के साथ मिलकर आयोजित विंटर वंडरलैंडए इस दिशा में एक और कदम थाए ताकि कड़ाके की सर्दियों में गर्म और ताज़े भोजन की खुशी उन लोगों तक पहुंचेए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।श् रॉबिन हुड आर्मी की नेशनल सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव वसुंधरा भंडारी ने कहाए शिस्वगी के साथ विंटर वंडरलैंड इस बात की याद दिलाता है कि जब संगठन और समुदाय एक साथ आते हैं तो करुणा कई गुना बढ़ जाती है। इस पहल के माध्यम से शहरों में हजारों बच्चों और कमजोर लोगों को सिर्फ भोजन ही नहींए बल्कि गर्माहटए देखभाल और साथ होने का एहसास भी मिला।

बजट से जनता निराश, सिर्फ नाम बदलने और घोषणाओं का खेलः शांति धारीवाल

कोटा (हुक्मनामा सामाचार)। राजस्थान सरकार के पेश किए गए बजट को पूर्व मंत्री एवं कोटा उत्तर से कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने 'हवा हवाई और कागजी बजट' करार दिया है। धारीवाल ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता को निराश करने वाला है, जिसमें कोई ठोस विजन या नई दिशा नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सिर्फ नाम बदलकर उन्हें दोबारा पेश कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर नई योजनाओं या ठोस प्रावधानों का अभाव है।धारीवाल ने खास तौर पर कोटा की अनदेखी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोटा से दो मंत्री होने और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद शहर के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई, जो बेहद दुखद है। कोटा में पर्यटन विकास को लेकर बजट में कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। चंबल रिवर फ्रंट के दूसरे फेज का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि इसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले बजट की कई घोषणाएं अब तक अधूरी हैं, ऐसे में नया बजट पेश करना केवल कागजी औपचारिकता है।